Kamal.Sandesh
kamalsandesh.org
KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-13
01-15 जुलाई, 2025 (पाक्षिक)
₹20

'आपातकाल लोकतंत्र पर सीधा हमला था'

'योग सबके लिए है'

नई दिल्ली में 23 जून, 2025 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

कर्तव्य पथ (नई दिल्ली) पर 21 जून, 2025 को 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

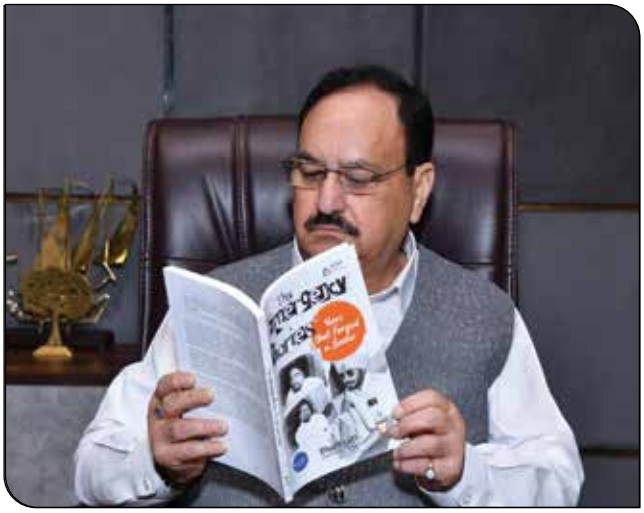

25 जून, 2025 को ब्लूक्राफ्ट द्वारा प्रकाशित 'द इमरजेंसी डायरीज: इयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर' पुस्तक पढ़ते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, यह पुस्तक श्री नरेन्द्र मोदी के शुरुआती वर्षों एवं आपातकाल के खिलाफ उनके संघर्ष के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है

नई दिल्ली में 25 जून, 2025 को 'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर 'द इमरजेंसी डायरीज: इयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर' पुस्तक का विमोचन करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

पचमढ़ी में 14 जून, 2025 को आयोजित मध्य प्रदेश भाजपा सांसद–विधायक प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्वागत करते मध्य प्रदेश भाजपा नेतागण

पचमढ़ी (मध्य प्रदेश) में 16 जून, 2025 को आयोजित भाजपा सांसदों एवं विधायकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **योग सबके लिए है, सीमाओं से, पृष्ठभूमि से, उम्र या क्षमता से परे है: नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर भारत और विश्व भर के लोगों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं...

09 **50 वर्ष बीत जाने के बाद भी कांग्रेस तानाशाही प्रवृत्ति से भरी हुई है : जगत प्रकाश नड्डा**
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा...

11 **प्रधानमंत्री ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को दी श्रद्धांजलि**
आपातकाल लागू होने के पचास साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जून को उन अनगिनत भारतीयों...

13 **'द इमरजेंसी डायरीज: ईयर दैट फॉर्ज्ड ए लीडर' पुस्तक का विमोचन**
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 25 जून, 2025 को नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित...

34 **प्रधानमंत्री को 'ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III' से अलंकृत किया गया**
साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने 16 जून को प्रधानमंत्री...

लेख

हमने दिखाया है कि आतंक को कैसे हराया जा सकता है / **राजनाथ सिंह** 24
सपनों से हकीकत तक / **अश्विनी वैष्णव** 26
श्रम शक्ति को सशक्त बनाने और भविष्योन्मुख भारत के 11 वर्ष / **डॉ. मनसुख मंडाविया** 28
धारा 370 के बाद बदलता कश्मीर / **शिवप्रकाश** 30
भारत सितारों पर पहुंचा और उनकी रोशनी को लेकर घर लौटा / **डॉ. जितेन्द्र सिंह** 32

अन्य

'द इमरजेंसी डायरीज़ - इयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर' का विमोचन 12
'संविधान की आत्मा की रक्षा देश की जनता की सामूहिक जिम्मेदारी है' 15
आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए नरेन्द्र मोदी का संघर्ष 17
मई, 2025 में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई 6 साल में सबसे कम 2.82% हुई 19
यह अकल्पनीय है कि विजयभाई हमारे बीच नहीं हैं: प्रधानमंत्री 20
ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को समझना जरूरी है: नरेन्द्र मोदी 21
प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा 22
प्रधानमंत्री की क्रोएशिया यात्रा 22
प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा 23
प्रधानमंत्री की ओडिशा यात्रा 23

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

हमने सेवा को संकल्प बनाया, जिसका परिणाम है कि आज देशभर के करोड़ों परिवारों को पीएम आवास से लेकर बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

(24 जून, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

25 जून, 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'आंतरिक अशांति' का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप कर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है, उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है।

(25 जून, 2025)

अमित शाह

मोदी जी ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' मनाने का निर्णय लिया, ताकि देश की स्मृति में रहे कि सरकार के तानाशाह बन जाने के कैसे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

(24 जून, 2025)

राजनाथ सिंह

भारत केवल अपने लिए नहीं सोचता, हम विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। पूरी दुनिया को परिवार मानना, उसके लिए काम करना हमारी सोच का हिस्सा है और योग इस सोच का practical expression है। भारत ने विश्व को शस्त्र नहीं, शास्त्र दिए हैं और योग यह हमारा सबसे प्रभावशाली शास्त्र है, जो न शोर करता है, न दिखावा, बस silently दुनिया को बदल रहा है।

(21 जून, 2025)

बी.एल. संतोष

भाजपा की प्राथमिक सदस्यता 14 करोड़ के पार हो गई है। बूथ स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ता ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। हालांकि हमने मेगा मैक्रो अभियान रोक दिया है, लेकिन बूथ स्तर की गतिविधि ने 14 करोड़ सदस्यता को पार करना संभव बनाया। बधाई #SanghatanParv2024

(21 जून, 2025)

मनोहर लाल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी इंजीनियरिंग क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहा है। चिनाब ब्रिज, अटल टनल, बोगीबील पुल जैसी संरचनाएं भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। पिछले 11 सालों में बुनियादी ढांचे के विकास ने भारत के हर कोने को एक-दूसरे से जोड़ा है।

(11 जून, 2025)

आपातकाल...

देश इंदिरा गांधी की इस क्रूरता को कभी नहीं भूल सकता

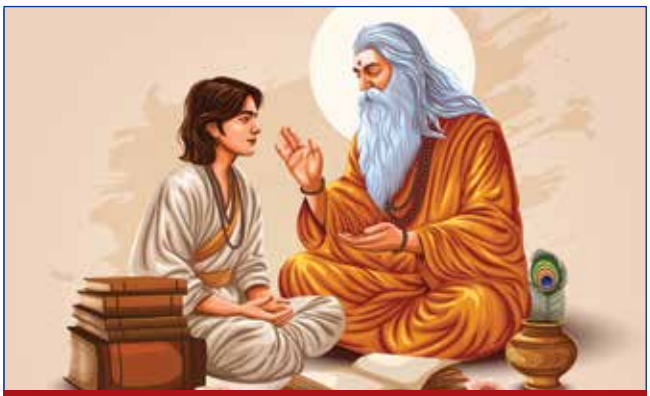

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
गुरु पूर्णिमा (10 जुलाई)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

आपातकाल : जब लोकतंत्र की हत्या हुई

आज जब पूरा विश्व 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, योग के महत्व को पूरी दुनिया में और भी अधिक स्वीकारा एवं अपनाया जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों में योग की बढ़ती लोकप्रियता को उभरते जनांदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक समाज जिन चुनौतियों को समस्त मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, योग जन-जन का आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक एवं शारीरिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर उनका समाधान प्रस्तुत करता है। योग से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षण के साथ-साथ सर्वांगीण विकास सुनिश्चित संभव है। यह विश्व को भारत का एक प्राचीन उपहार है जो मानव-कल्याण को समर्पित है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 177 देशों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जहां यह संख्या अभूतपूर्व थी, वहीं 193 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर इसे सर्वसम्मति से पारित किया जो एक रिकॉर्ड है। जहां पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को अद्भुत उत्साह के साथ मना रहा है, वहीं भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनैतिक कारणों से इस राष्ट्रीय उपलब्धि को स्वीकार करने से हिचकते हैं। जहां इस प्रकार की मानसिकता उन्हें निरंतर राजनैतिक हाशिए पर ले जा रही है, वहीं योग दिनोंदिन और अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है।

> **आधुनिक समाज जिन चुनौतियों को समस्त मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, योग जन-जन का आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक एवं शारीरिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर उनका समाधान प्रस्तुत करता है**

आपातकाल के 50वें वर्ष को पूरे देश ने 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाया। संविधान हत्या दिवस', यह नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय इतिहास के उन काले पन्नों के लिए सटीक प्रतीत होता है, जब लोकतंत्र की हत्या हुई थी तथा देश पर तानाशाही थोपने के प्रयास हुए थे। मौलिक अधिकारों का गला घोंट दिया गया था, विपक्ष के नेता जेलों में डाल दिए गए थे। मीडिया पर सेंसरशिप लागू किया गया था। न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए थे, संविधान की आत्मा को कुचलकर संसद को पंगु बना दिया गया था। यह सर्व-स्वीकार्य तथ्य है कि देश पर आपातकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्सी को बचाने के लिए लगाया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का सांसद के रूप में निर्वाचन अवैध घोषित कर उन्हें छह वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली, तब इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया। उन काले दिनों में पूरा देश एक बड़े जेलखाने में बदल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीस, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, मधु दंडवते एवं अरुण जेटली जैसे विपक्ष के वरिष्ठ नेता जेल में डाल दिए गए। एक अनुमान के अनुसार 3 लाख से अधिक लोग पूरे देश में गिरफ्तार किए गए तथा 30 हजार से अधिक लोग काला कानून 'मीसा' के अंतर्गत बंदी बनाए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल के विरुद्ध पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐतिहासिक आंदोलन हुए तथा आंदोलन में शामिल लोगों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। बड़ी संख्या में लोगों को अपने प्राणों की आहुतियां भी देनी पड़ीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उस दौर में आपातकाल के विरुद्ध भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। देश की लोकतांत्रिक शक्तियों के एकजुट एवं अथक संघर्ष के कारण देश में लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ। आम चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की करारी हार हुई।

जहां, सभी लोकतांत्रिक शक्तियों के गैर-समझौतावादी व अटल एवं अडिग रहने वाले संघर्षों के परिणामस्वरूप लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ वहीं देश के सामने आज भी लोकतंत्र विरोधी राजनैतिक मानसिकता की चुनौती समाप्त नहीं हुई है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के कई राजनैतिक दल पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हो गए हैं तथा किसी न किसी वंश, परिवार या स्वार्थी तत्वों के समूह के बंधक बने हुए हैं। वे देश पर पुनः तानाशाही थोपने के लिए सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। 'संविधान हत्या दिवस' न केवल पूर्व में हुए ऐसे कुप्रयासों की याद दिलाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए दिए गए बलिदानों एवं संघर्षों का स्मरण भी दिलाता है। राष्ट्र को लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहकर लोकतांत्रिक मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए भविष्य में तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध एकजुट रहना पड़ेगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

योग सबके लिए है, सीमाओं से, पृष्ठभूमि से, उम्र या क्षमता से परे है: नरेन्द्र मोदी

आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापत्तनम के मनमोहक समुद्र तट पर सुनहरी सुबह और बंगाल की खाड़ी में ताल से ताल मिलाती तरंगों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून को 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में देश-दुनिया भर के योग प्रेमियों का नेतृत्व किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा योग सम्मेलन बन गया, जो योग की सार्वभौमिक स्वीकार्यता तथा समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है। योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें विश्व के साथ एकरूपता की दिशा में ले जाता है, यह हमें सिखाता है कि हम अलग-थलग नहीं, बल्कि प्रकृति का ही हिस्सा हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर भारत और विश्व भर के लोगों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने रेखांकित किया कि इस वर्ष 11वां अवसर है जब विश्व 21 जून को सामूहिक रूप से योग का अभ्यास करने के लिए एकत्रित हुआ है। उन्होंने कहा कि योग का सार 'एकजुट होना' है और यह देखना उत्साहजनक है कि योग ने विश्व को कैसे एकजुट किया है। पिछले एक दशक में योग की यात्रा पर विचार करते हुए श्री मोदी ने उस क्षण का स्मरण किया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के विचार का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि 175 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जो इतनी व्यापक वैश्विक एकता का एक दुर्लभ उदाहरण है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह समर्थन केवल एक प्रस्ताव के लिए नहीं था, बल्कि इसने मानवता की भलाई के लिए दुनिया द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व किया।

योग विश्व भर में लाखों लोगों की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा

श्री मोदी ने कहा, "11 वर्ष बाद योग विश्व भर में लाखों लोगों की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बन गया है।" प्रधानमंत्री ने यह देखकर गर्व व्यक्त किया कि कैसे दिव्यांग व्यक्ति ब्रेल में योग संबंधी पुस्तकें पढ़ रहे हैं और कैसे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने योग ओलंपियाड में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे वह सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हों, माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या समुद्र का विशाल विस्तार हो, संदेश एक ही है, "योग सभी के लिए है, सीमाओं से परे, पृष्ठभूमि से परे, उम्र या क्षमता से परे है।"

विशाखापत्तनम में होने पर संतोष व्यक्त करते हुए और शहर को प्रकृति तथा प्रगति का संगम बताते हुए श्री मोदी ने कार्यक्रम के

प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम में 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया

शानदार आयोजन के लिए लोगों की सराहना की और श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री पवन कल्याण को उनके नेतृत्व के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने एक उल्लेखनीय पहल— योगांध्रा अभियान शुरू किया। उन्होंने श्री नारा लोकेश के प्रयासों की भी विशेष रूप से सराहना की और कहा कि उन्होंने प्रदर्शित किया है कि कैसे योग एक सच्चा सामाजिक उत्सव हो सकता है और कैसे समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल किया जा सकता है।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक से डेढ़ महीने में श्री लोकेश ने योगांध्रा अभियान के माध्यम से अनुकरणीय प्रतिबद्धता दिखाई है और अपने प्रयासों के लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगांध्रा अभियान में दो करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए हैं, जो जन भागीदारी की जीवंत भावना को दर्शाता है।

'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग'

इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह थीम एक गहन सत्य को दर्शाती हैः पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का स्वास्थ्य परस्पर जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मानव कल्याण, हमारे भोजन को पैदा करने वाली मिट्टी, हमारे पानी की आपूर्ति करने वाली नदियों, हमारे इकोसिस्टम को साझा करने वाले पशुओं और हमें पोषण देने वाले पौधों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि योग हमें इस अंतर्संबंध के प्रति जागरूक करता है और हमें विश्व के साथ एकरूपता की दिशा में ले जाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "योग हमें सिखाता है कि हम

आज 11वें 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर हमारे योगप्रेमी भाई-बहनों के साथ योगाभ्यास किया। योग हमारे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों आयामों को संतुलन व स्वास्थ्य प्रदान कर सुखी और श्रेष्ठ जीवन सुनिश्चित करता है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल से योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, जिसका परिणाम है कि बीते 10 वर्षों में दुनियाभर में लोग योग के प्रति सजग हुए और आज योग को अपने दैनिक जीवन में अपना रहे हैं। आप सभी को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

—जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

उधमपुर में उत्तरी कमान मुख्यालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। योग शांति प्रदान करता है। यह एक कला है, एक विज्ञान है, एक दर्शन है और आध्यात्मिकता है। जो लोग अपने दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करते हैं, वे अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखते हैं। यह हमें सकारात्मक और सक्रिय बनाता है।

—राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

मन, शरीर और मस्तिष्क में एकात्मता लाने वाला 'योग' आज विश्वभर में लोगों की दिनचर्या का अंग बन चुका है। 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के अवसर पर अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया।

—अमित शाह, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

अलग-थलग व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। शुरुआत में हम अपने स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल करना सीखते हैं, लेकिन धीरे-धीरे यह देखभाल हमारे पर्यावरण, समाज और पूरे विश्व तक फैल जाती है। योग एक गहन व्यक्तिगत अनुशासन है, जो एक सामूहिक प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है— यह व्यक्तियों को मैं से हम में रूपांतरित करता है।"

उन्होंने भारतीय संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हमें 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का मूल्य सिखाती है— सभी का कल्याण व्यक्ति का पवित्र कर्तव्य है और 'मैं' से 'हम' की यह यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह-अस्तित्व का आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही सोच सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है।

मोटापे की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए और इसे एक बढ़ती वैश्विक चुनौती बताते हुए श्री मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर अपनी विस्तृत चर्चा को याद किया, जिसमें उन्होंने खान-पान में 10 प्रतिशत तक तेल की खपत कम करने की चुनौती का उल्लेख किया था। श्री मोदी ने भारत और विश्व भर के नागरिकों से इस पहल में शामिल होने की अपनी अपील दोहराई।

प्रत्येक समाज तनाव से मुक्त होने के लिए अपनाए 'योग'

श्री मोदी ने सभी से योग को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान करते हुए कहा कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव की ओर ले जाएगा। उन्होंने आग्रह किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन का आरंभ योग से करे ताकि जीवन में संतुलन आए और प्रत्येक समाज तनाव से मुक्त होने के लिए योग को अपनाए। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए समापन किया, "योग को मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम करना चाहिए, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग को वैश्विक संकल्प बनना चाहिए।"

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पारित करवाने का अभूतपूर्व कदम उठाया। श्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि इस आंदोलन के एक दशक पूरे होने के अवसर पर हमने इस वर्ष 10 प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें वृक्षारोपण के साथ हरित योग (ग्रीन योग), योग कनेक्ट, योग पार्क, योग बंधन, योग महाकुंभ और योग संगम शामिल हैं, जिन्हें देश भर में 10 लाख से अधिक संगठन मना रहे हैं।

आंध्र प्रदेश को इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाया, जिसमें विशाखापत्तनम में 3 लाख से अधिक नागरिकों ने सामूहिक योग प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, "कार्यक्रम का समापन महीने भर चले सफल योगांध्र अभियान के साथ हुआ, जिसमें राज्य भर में 2.17 करोड़ प्रतिभागियों ने भाग लिया और कई रिकॉर्ड बनाए।"

9 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के नौ लाख से अधिक कैडेटों ने 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए देश भर के प्रतिष्ठित स्थानों पर समन्वित योग सत्रों में भाग लिया, जो स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति राष्ट्र की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में द्वारका से लेकर पूर्व में तेजू तक भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित और दर्शनीय स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, चेन्नई में मरीना बीच, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लेह में शांति स्तूप, ब्रह्मपुत्र के तट, गुवाहाटी और जम्मू-कश्मीर में डल झील के साथ-साथ देश भर के सार्वजनिक पार्कों, स्कूलों और कॉलेजों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर योग संगम कार्यक्रम

योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किए गए। इस वर्ष 'माईगॉव' और 'माईभारत' जैसे प्लेटफार्मों पर 'योग विद फैमिली' और 'योग अनप्लग्ड' के तहत युवा-केंद्रित पहल जैसी विशेष प्रतियोगिताएं आरंभ की गई हैं, जो व्यापक स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं।

इस वर्ष की थीम 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' मानव और संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को रेखांकित करती है और सामूहिक कल्याण की वैश्विक दृष्टि को प्रतिध्वनित करती है, जो भारत के 'सर्वे संतु निरामया' (सभी रोग मुक्त हों) के दर्शन में निहित है। ■

'संविधान हत्या दिवस'

50 वर्ष बीत जाने के बाद भी कांग्रेस तानाशाही प्रवृत्ति से भरी हुई है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 25 जून, 2025 को नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में 'संविधान हत्या दिवस' पर मीडिया को दिए गए अपने संबोधन में कहा कि 25 जून, 1975 को लगाया गया आपातकाल लोकतंत्र पर सीधा हमला था। श्री नड्डा ने कांग्रेस पर तानाशाही मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर संविधान को रौंद डाला, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आपातकाल के दौरान कांग्रेस की भूमिका की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आज भी कांग्रेस परिवारवाद, व्यक्तिवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य कर रही है। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री नड्डा ने कहा कि भारत विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उन घटनाओं को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन, कांग्रेस सरकार की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 50 वर्ष पहले आपातकाल की घोषणा की थी। यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला और कुठाराघात था। 25 जून, 1975 की आधी रात को, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी कांग्रेस आज उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी तानाशाही प्रवृत्ति से भरी हुई है।

उन्होंने कहा कि 1975 में कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचारसंहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों-रात प्रेस की बिजली काट दी गई, समस्त विपक्ष को जेल में डाल दिया गया और प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। कांग्रेस की तानाशाही का विरोध केवल राजनीतिक नहीं था, यह भारत की आत्मा और संविधान की रक्षा का आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवादियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। श्री जयप्रकाश नारायण जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी सहित पार्टी एवं विचार परिवार के हजारों कार्यकर्ताओं को इंदिरा गांधी की सरकार ने जबरन जेल में डाल दिया था।

1975 में कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचारसंहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए, 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों-रात प्रेस की बिजली काट दी गई, समस्त विपक्ष को जेल में डाल दिया गया और प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया

श्री नड्डा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तानाशाही सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए लाखों समर्पित स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सच्चाई को हर गांव, हर गली, हर घर तक पहुंचाया था। आपातकाल के संघर्ष और अनसुनी घटनाओं की कहानियों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुस्तक The Emergency Diaries: Years That Forged a Leader में शब्दों में पिरोया है।

उन्होंने कहा कि आपातकाल का दंश याद रखना और याद दिलाना, दोनों जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस आज भी उसी तानाशाही मानसिकता के साथ जी रही है। हम सबको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए कि किस प्रकार कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को कुचलने की साजिश रची थी। लोकतंत्र के उपासकों ने किस प्रकार अपने प्राणों की परवाह न करते हुए संघर्ष को प्रकाशित कर कांग्रेस की इस साजिश को विफल किया था। 'इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया' जैसे नारे कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाते थे, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने देश को व्यक्तिवाद और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस समझती है कि इस देश की सत्ता पर केवल एक और एक परिवार का ही हक है। तभी तो उसने अपनी सरकार के प्रधानमंत्री के ऊपर भी सुपर पीएम बिठा दिया था। आज भी कांग्रेस की मानसिकता वैसी ही है। एक गरीब का देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना कांग्रेस से हज़म नहीं हो रहा है। कांग्रेस-शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का हाल आज भी वही है, जो आपातकाल में था। विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण और सत्ता का अहंकार खुलेआम दिखता है। इंदिरा गांधी जी ने जस्टिस एच.आर. खन्ना जैसे ईमानदार जज को सीनियर होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने इंदिरा सरकार के खिलाफ़ फैसला सुनाया था। कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया था कि जो भी अधिकारी या जज उनके इशारों पर न चले, उन्हें या तो हटा दिया जाए या तबादला कर दिया जाए। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को महफ़ूज़ रखने के लिए संविधान में अलोकतांत्रिक संशोधन कर उसकी मूल आत्मा को ही बदल दिया था। आपातकाल के दौरान यदि किसी नागरिक को गोली मार दी जाए, तब भी उसे अदालत में जाने का अधिकार नहीं था।

श्री नड्डा ने कहा कि आज राहुल गांधी और कांग्रेस संविधान की झूठी दुहाई दे रहे हैं। आपातकाल के दौरान जेलों में बंद लोगों को अपने परिजनों के अंतिम क्रिया-कर्म में शामिल होने तक की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस ने आज तक आपातकाल लगाने और अपने किए पर कभी माफी नहीं मांगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बाकायदा बहिष्कृत पत्रकारों की सूची जारी की थी, जिनकी डिबेट में भागीदारी पर कांग्रेस प्रवक्ताओं को रोक दिया गया था। जहां एक ओर वे अपने शासन में पत्रकारों पर मुकदमा करते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष में होने पर उनका बहिष्कार करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से

प्रधानमंत्री ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को दी श्रद्धांजलि

आपातकाल विरोधी आंदोलन ने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को संरक्षित रखने की महत्ता की फिर से पुष्टि की: नरेन्द्र मोदी

आपातकाल लागू होने के पचास साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जून को उन अनगिनत भारतीयों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जो देश के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में डटे रहे।

संवैधानिक मूल्यों पर हुए गंभीर हमले को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है— एक ऐसा दिन जब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था और अनगिनत राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था।

श्री मोदी ने संविधान में निहित सिद्धांतों को मजबूत करने तथा 'विकसित भारत' की कल्पना को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने कहा कि आपातकाल विरोधी आंदोलन एक सीखने वाला अनुभव था, जिसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को संरक्षित रखने के महत्व की पुष्टि की।

श्री मोदी ने आपातकाल के काले दिनों को याद रखने वाले या उस दौरान जिन परिवारों ने कष्ट सहा, उन सभी लोगों का आह्वान किया कि वे अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करें, ताकि युवाओं में 1975 से 1977 तक के शर्मनाक समय के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

'एक्स' पर अनेक पोस्ट में उन्होंने लिखा; "आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक, आपातकाल लागू होने के पचास साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ़्त में ले लिया हो!"

"कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल पाएगा कि किस तरह हमारे संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया, संसद की आवाज़ दबा दी गई और अदालतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 42वां संशोधन उनके छल-कपट का एक प्रमुख उदाहरण है।

25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है— एक ऐसा दिन जब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था और अनगिनत राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था

गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और दलितों को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जिसमें उनकी गरिमा का अपमान भी शामिल है।"

"हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं! इनमें पूरे भारत से, हर क्षेत्र से, अलग-अलग विचारधाराओं से आए लोग थे जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक-दूसरे के साथ मिलकर काम किया: भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह उनका सामूहिक संघर्ष ही था जिसने सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े, जिसमें वे बुरी तरह हार गए।"

"हम अपने संविधान में निहित सिद्धांतों को मजबूत करने और एक 'विकसित भारत' के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं और गरीबों और वंचितों के सपनों को पूरा करें।" ■

उन लोकतंत्र के सच्चे सिपाहियों को श्रद्धांजलि और धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिन्होंने आपातकाल जैसे अभिशाप से देश को मुक्त कराने के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने न केवल संविधान की रक्षा की, बल्कि देश की भी रक्षा की।

मुख्य बिंदु

- आज ही के दिन, 50 वर्ष पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। यह एक ऐसा कदम था जिसे देश आज भी लोकतंत्र के काले अध्याय और संविधान की आत्मा पर पड़े गहरे आघात के रूप में याद करता है।
- आपातकाल की 50वीं बरसी पर संविधान की हत्या को याद रखना और दूसरों को याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता आज भी जारी है।
- आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तानाशाह सरकार को चुनौती दी और लाखों स्वयंसेवकों के साथ कांग्रेस की सच्चाई हर गांव-गली तक पहुंचाई।
- कांग्रेस अब भी मानती है कि देश की सत्ता पर सिर्फ एक परिवार का हक है। उसने अपने प्रधानमंत्री पर भी 'सुपर पीएम' बैठाया था। एक गरीब परिवार के व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना कांग्रेस को हज़म नहीं हो रहा।
- 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने उन पत्रकारों की सूची जारी की, जिनसे उसके प्रवक्ताओं को डिबेट में न जाने को कहा गया। सत्ता में रहते हुए पत्रकारों पर मुकदमे और विपक्ष में रहते हुए उनका बहिष्कार कांग्रेस की दोहरी नीति है।
- इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान में ऐसे अलोकतांत्रिक संशोधन किए, जिससे उसकी मूल आत्मा ही बदल गई। आपातकाल में हालात ऐसे थे कि अगर किसी नागरिक को गोली भी मार दी जाए, तो वह अदालत नहीं जा सकता था।
- कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और संविधान की रक्षा का आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवादियों ने जान की बाजी लगा दी। ■

'द् इमरजेंसी डायरीज़ – इयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर' का विमोचन

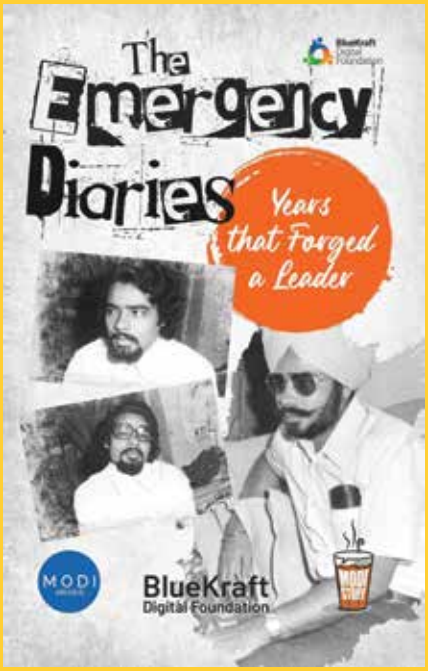

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ब्लूक्राफ्ट प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक, 'द् इमरजेंसी डायरीज़ - इयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर' का विमोचन 25 जून, 2025 को नई दिल्ली में किया। यह पुस्तक श्री नरेन्द्र मोदी, जो उस समय रा.स्व. संघ के एक युवा प्रचारक थे, द्वारा आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालती है। उनके साथ काम करने वाले सहयोगियों के प्रत्यक्ष अनुभवों और समृद्ध अभिलेखीय सामग्री का उपयोग कर लिखी गई यह पुस्तक एक अद्वितीय और गहन परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। यह अपनी तरह का पहला कार्य है जो एक ऐसे युवा व्यक्ति के प्रारंभिक वर्षों पर महत्वपूर्ण रूप से शोध करने में योगदान देता है, जिसने खुद को पूरी तरह से सत्तावाद के विरुद्ध संघर्ष में समर्पित कर दिया था।

पुस्तक के विमोचन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक्स' पर कई पोस्ट में कहा, "जब आपातकाल लगाया गया था, तब मैं एक युवा आरएसएस प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को संरक्षित करने की महत्ता की पुष्टि की। साथ ही, मुझे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुशी है कि ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने उन अनुभवों में से कुछ को एक किताब के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी ने लिखी है, जो खुद आपातकाल विरोधी आंदोलन के एक दिग्गज थे।

'द् इमरजेंसी डायरीज़' आपातकाल के वर्षों के दौरान मेरी यात्रा का वृत्तांत है। इसने उस समय की कई यादें ताज़ा कर दीं। मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूं जिन्हें आपातकाल के वह काले दिन याद हैं या जिनके परिवारों ने उस दौरान कष्ट झेले थे, वे अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करें। इससे युवाओं में 1975 से 1977 तक के शर्मनाक समय के बारे में जागरूकता पैदा होगी।" ■

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर एक काला अध्याय था, जिसे याद रखना जरूरी है ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो : अमित शाह

'द् इमरजेंसी डायरीज: ईयर दैट फॉर्ज्ड ए लीडर' पुस्तक का विमोचन

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 25 जून, 2025 को नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम 'संविधान हत्या दिवस' पर 'द् इमरजेंसी डायरीजः ईयर दैट फॉर्ज्ड अ लीडर' पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें उस दौर के दुःखद अनुभवों और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका विस्तार से दर्ज है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर एक काला अध्याय था, जिसे याद रखना जरूरी है ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। इमरजेंसी के दौरान मीडिया, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और आपातकाल के खिलाफ मुखर आवाज रहे प्रोफेसर श्री रामबहादुर राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

'संविधान हत्या दिवस' मनाने का निर्णय

श्री शाह ने कहा कि कहा जाता है कि कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, यह बात व्यक्तिगत जीवन में उचित भी हो सकती है लेकिन जब विषय समाज और राष्ट्र का हो, तो ऐसी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, ताकि उनकी पुनरावृत्ति न हो सके। इसी उद्देश्य से देश के युवाओं को संस्कारित, संगठित और संघर्षशील बनाए रखना आवश्यक है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जब इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया तब नाम को लेकर अनेक विचार आए, कुछ लोगों को लगा कि 'संविधान हत्या दिवस' शब्द कुछ कठोर और निर्मम प्रतीत होता है, परंतु गंभीर विचार-विमर्श के पश्चात् यह नाम इसलिए तय किया गया, क्योंकि आपातकाल के दौरान देश को एक विशाल जेलखाना बना दिया गया था। देश की आत्मा को मूक कर दिया गया था, न्यायपालिका के कान बंद कर दिए गए थे और लेखनी से स्याही छीन ली गई थी। उस पूरे कालखंड का वर्णन ऐसे ही कठोर शब्दों के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी यह जान सके कि वास्तव में उस समय क्या हुआ था।

'द् इमरजेंसी डायरीज: ईयर दैट फॉर्ज्ड अ लीडर' पुस्तक

श्री शाह ने कहा कि इस अवसर पर 'द् इमरजेंसी डायरीजः ईयर दैट फॉर्ज्ड अ लीडर' नामक पुस्तक का विमोचन भी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आपातकाल कालखंड के अनुभवों का वर्णन है। उस समय वे एक युवा संघ प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर 19 महीनों तक चले आंदोलन का हिस्सा रहे। उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चल रहे जन-आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मीसा के तहत जेल में डाले गए बंदियों के परिजनों से मिले, उनकी समस्याएं सुनीं और उनके इलाज की व्यवस्था की। उन्होंने गुप्त समाचार पत्रों को बाजारों, चौराहों, विद्यार्थियों और महिलाओं में वितरित किया एवं गुजरात में संघर्ष का नेतृत्व किया। यह सब उन्होंने मात्र 24–25 वर्ष की आयु में किया था, जिसकी पूरी कथा इस पुस्तक में समाहित है। पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की भूमिका, लोक संघर्ष समिति के प्रयास, सत्याग्रह और जनजागरण की कठिनाइयों का भी उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उस समय भूमिगत रहकर कार्य कर रहे थे। उन्होंने कभी साधु, कभी सरदार, कभी अगरबत्ती विक्रेता तो कभी अखबार वितरक का रूप धारण कर कार्य किया।

उन्होंने कहा कि जब विधाता न्याय करता है, तो वह अपने तरीके से करता है। जिस 25 वर्ष के युवक ने उस समय कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर-घर, गांव-गांव जाकर, शहरों में घूम-घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। जिस परिवारवाद को स्थापित करने के

लिए आपातकाल थोपा गया था, उसी व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से परिवारवाद को उखाड़ फेंका। यह पुस्तक पांच अध्यायों में विभाजित है : मीडिया की सेंसरशिप, सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों की पीड़ा का वर्णन और तानाशाही से जन भागीदारी तक की यात्रा। विशेष रूप से देश के युवाओं को यह पुस्तक एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। किशोरावस्था के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, आज वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बन चुका है।

आपातकाल की बर्बरता और संपूर्ण क्रांति आंदोलन

श्री शाह ने कहा कि 24 जून, 1975 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया और एक तानाशाही सोच को जमीन पर उतारने का अध्यादेश अस्तित्व में आया। कई बार इतिहास केवल घटनाओं को नहीं बताता, वह नीयत और नजरिए को भी उजागर करता है। बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना 2,67,000 शब्द बोलकर चर्चाओं के माध्यम से की, उन सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा गांधी ने एक वाक्य बोलकर कर दिया कि 'राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है।' इस एक वाक्य ने संविधान की आत्मा को खत्म कर दिया और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। आपातकाल लगाने का मूल कारण भी 12 जून का वह फैसला था। 12 जून को दो घटनाएं एक साथ हुईं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया और उन्हें छह साल तक चुनाव न लड़ने योग्य घोषित कर दिया। पूरे देश में सन्नाटा छा गया और सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे मिला और उसी दिन यानी 12 जून को गुजरात में जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार बनाई। इससे घबराकर 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। कारण यह बताया गया कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि खतरा राष्ट्र की सुरक्षा को नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की कुर्सी को था।

श्री शाह ने कहा कि जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झकझोर दिया था। गुजरात से शुरू हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा, गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस हटी और विपक्षी एकजुट हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। यह इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। जेपी आंदोलन में महंगाई के खिलाफ छात्र एकत्रित हुए, अन्याय के खिलाफ रेल कर्मचारी एकजुट हुए, जगह-जगह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ और अंत में 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से जब स्टे मिला, उसी रात इमरजेंसी लगाकर स्टे देने वाली कोर्ट को भी चुप करा दिया गया, अखबारों को भी चुप करा दिया और आकाशवाणी को भी चुप करा दिया गया। 1,10,000 सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल की कालकोठरी में बंद कर दिया गया। सुबह 4:00 बजे कैबिनेट बुलाई गई, कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ और आपातकाल की घोषणा कर दी गई।

उन्होंने कहा कि शाह कमीशन ने पूरी जांच के बाद कहा कि डिटेंशन, नसबंदी और तोड़फोड़ के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे देश में भय और आतंक का वातावरण बना, उसका कोई भी उदाहरण विश्व में नहीं मिलता। श्रीमती विजयाराजे सिंधिया, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, श्री राजनारायण, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, आचार्य कृपलानी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री अरुण जेटली, श्री जयकिशन गुप्ता, श्री सत्येंद्र नारायण सिंह, गायत्री देवीजी, श्री मुलायम सिंह यादव और डीएमके के नेताओं को बिना किसी अपराध के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 253 पत्रकार गिरफ्तार हुए, 29 विदेशी पत्रकारों को देश के बाहर भेज दिया गया और कई सारे अखबारों ने संपादकीय को खाली रखकर इसके सामने विरोध दर्ज कराया, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता प्रमुख था। उनकी बिजली काट दी गई और संसदीय कार्यवाही पर भी सेंसर लगा दिया गया। न्यायालयों को भी नियंत्रित कर दिया गया। देशभर में लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गए। संविधान में 38वां, 42वां संशोधन कर अनुच्छेद 223-ए, 223-बी में बदलाव किए गए और इसके साथ-साथ अनुच्छेद 123, 213, 352, 519 और अनुच्छेद 356 का उपयोग कर लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया गया।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में सरकार के खिलाफ फैसले देने वाले जजों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से रोका गया। उसके पहले के और वरिष्ठता में आगे तीन-तीन न्यायाधीशों को दरकिनार कर जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। श्री शाह ने कहा कि किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया गया। मनोज कुमार की फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, देव आनंद को दूरदर्शन से प्रतिबंधित किया गया और यहां तक कि 'आंधी' और 'किस्सा कुर्सी का' फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया।

'भारत प्रथम' सोच की जनमानस में गूंज

श्री शाह ने कहा कि संविधान की हत्या करने के बाद इसे मौन कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई और बाद में एक दिन विपक्ष को झांसा देने के चक्कर में इमरजेंसी को समाप्त किया गया। देश में चुनाव आया। सारी विपक्षी पार्टियां श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एकत्रित हुईं और देश की जनता ने तानाशाही मानसिकता वाली इंदिरा गांधी को ऐसा दंड दिया कि वह स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गईं और देश में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। यह दिन इसलिए याद रखना आवश्यक है कि भविष्य में कभी भी कोई व्यक्ति तानाशाही सोच को इस देश के संविधान पर थोप न सके और इसी कारण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस दिन को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उस वक्त पनपे "राष्ट्र से बड़ी पार्टी है, पार्टी से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा मैं हूं और देशहित से बड़ी सत्ता है" के विचार के विपरीत आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'भारत प्रथम' की सोच पूरी देश के जनमानस में गूंज रही है। ■

'संविधान की आत्मा की रक्षा जनता की सामूहिक जिम्मेदारी है'

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 24 जून, 2025 को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में 'आपातकाल के 50 वर्ष' की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। आपातकाल जैसी घटना ने लोकतंत्र की नींव को हिला दिया था यदि उसकी स्मृति समाज के मन से मिटने लगे, तो यह किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसी घटनाओं की स्मृति युवाओं और किशोरों की चेतना से धीरे-धीरे मिटने लगती है, तब इस प्रकार की संगोष्ठियां और 'संविधान हत्या दिवस' जैसे आयोजन उस स्मृति को पुनर्जीवित करने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अनिर्बान गांगुली और पाञ्चजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

तुगलकी फरमान

श्री शाह ने कहा कि दस्तावेजों में भले ही पचास साल बीत चुके हों, परंतु करोड़ों भारतीयों के मन में उस समय की स्मृति आज भी उतनी ही ताजा है जितनी 24 जून 1975 की रात को थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास की वह रात शायद सबसे लंबी थी और एक प्रकार से सबसे छोटी भी। सबसे लंबी भी इसलिए, क्योंकि इस रात की सुबह पूरे 21 महीने बाद आई। 21 महीनों के बाद ही देश में फिर से लोकतंत्र लौटा और सबसे छोटी इसलिए, क्योंकि जिन अधिकारों को स्थापित करने के लिए विधिक प्रक्रिया, संसद की गरिमा और नागरिक सम्मान की रक्षा हेतु जो नियम बनाए गए थे, जिनका निर्माण दो वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में हुआ, उन्हें एक झटके में नष्ट कर दिया गया। हमारे संविधान का निर्माण एक तपस्या था। इसमें 13 समितियां बनीं, 11 सत्रों में 165 दिनों की चर्चा हुई, 163 दिनों में 114 दिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर व्यापक बहस हुई। कुल 1100 घंटे और 32 मिनट चर्चा हुई, सात सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमिटी ने उसे अंतिम रूप दिया। यह संविधान, जो विचार और विमर्श में दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक संविधान से कहीं अधिक गहरा और परिश्रम से बनाया गया था, उसे एक 'किचन कैबिनेट' के तुगलकी फरमान ने एक ही मिनट में खारिज कर दिया।

संविधान की आत्मा की हत्या

श्री शाह ने कहा कि एक बहुदलीय लोकतांत्रिक देश के मूल स्वभाव को एक व्यक्ति की तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र ही 'आपातकाल' है। इस षड्यंत्र को उस समय बहुत से लोगों ने पुरजोर विरोध किया। उस काली रात की सुबह ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया।

उन्होंने कहा कि 25 जून, 1975 की सुबह सूरज तो उगा लेकिन उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। उस सुबह मौलिक अधिकारों की चादर ओढ़े नागरिक तानाशाही की जंजीरों में बंधे हुए नींद से जगे थे। उस सुबह ठीक आठ बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी कि 'राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा की है।'

कांग्रेस से सवाल

श्री शाह ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सवाल पूछे कि क्या आपातकाल जैसे निर्णय के लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या विपक्ष या देशवासियों को विश्वास में लिया गया था? आज लोकतंत्र की खोखली बातें कर रहे लोग उसी पार्टी से जुड़े हैं जिसने लोकतंत्र के रक्षक की नहीं बल्कि भक्षक की भूमिका निभाई थी। आपातकाल के लिए कारण बताया गया राष्ट्र की सुरक्षा, जबकि वास्तविक कारण था अपनी सत्ता की सुरक्षा, क्योंकि जब इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने उनके चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, तब कोर्ट ने उनके (इंदिरा गांधी) चुनाव को निरस्त कर दिया और कहा कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का

दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर उन्हें स्थगन तो प्रदान कर दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वे प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, परंतु संसद में मतदान नहीं कर सकतीं और सांसद के रूप में कोई अधिकार नहीं ले सकतीं। इसके बाद इंदिरा गांधी ने नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इसी संवैधानिक परिस्थिति का सहारा लेकर, संविधान की धाराओं को ही तोड़-मरोड़कर संविधान की आत्मा की हत्या की। उस समय देश में न कोई बाहरी सुरक्षा का संकट था, न कोई आंतरिक संकट। देश महंगाई से जूझ रहा था। गुजरात में छात्रों ने सबसे पहले विरोध की मशाल जलाई, जो बिहार तक पहुंच गई। जेपी आंदोलन शुरू हुआ, रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और जगह-जगह कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाजें उठने लगीं। मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठ गए और देश की जनता जाग उठी थी। बहुमत के नशे में चूर इंदिरा गांधी की सत्ता की कुर्सी डगमगाने लगी थी। एक व्यक्ति ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया गया। सुबह 4 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। तत्कालीन कैबिनेट सदस्य बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह ने बाद में कहा कि 'जब हम बैठक में पहुंचे, तो हमें न कोई एजेंडा बताया गया, न कोई विचार-विमर्श हुआ, केवल सूचना दी गई।' गृह सचिव को बुलाकर आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी गई।

संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग

श्री शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया। अनुच्छेद 352 का उद्देश्य देश पर गंभीर संकट आने की स्थिति में आपातकाल लागू करना था, किंतु इंदिरा गांधी ने उसी अनुच्छेद का प्रयोग कर केवल सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू कर दिया। इस आपातकाल के दौरान 1,10,000 से अधिक विपक्षी राजनीतिक नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। केवल नेता ही नहीं, पत्रकार, संपादक, रिपोर्टर, छात्र नेता, समाजसेवी सभी को जेल में बंद कर दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस, मीडिया, कलाकार और आम जन सभी स्तब्ध रहकर यह दृश्य देख रहे थे। आगे चलकर गुजरात और तमिलनाडु की गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने का भी प्रयास किया गया।

उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जो संविधान संशोधन हुए, उनमें 38वां संशोधन प्रमुख था, जिसके तहत अनुच्छेद 130 और 213 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 352 द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। फिर अनुच्छेद 329 में संशोधन कर प्रधानमंत्री को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया। इसके साथ ही अनुच्छेद 323ए और 323बी के माध्यम से प्रशासनिक मामलों को देखने वाले न्यायाधिकरणों को सरकार के नियंत्रण में ला दिया गया। अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया और अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की अवधि को बढ़ा दिया गया। संसद की सीमाएं भी बढ़ा दी गईं और व्यापक प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ। तिहाड़ जेल में ही 4000 लोग मीसा के तहत बंद थे, जबकि जेल की क्षमता सिर्फ 1200 की थी। एक करोड़ से अधिक लोगों की जबरन नसबंदी की गईं। लता मंगेशकर जी ने ऐसे गाने गाए, जिनमें पुरुष और महिला दोनों की आवाजें उन्हीं की थीं, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज को आकाशवाणी से बैन कर दिया गया था। न्याय का यह काल और लंबा चलता, अगर चाटुकारिता ही अंत का कारण न बनती। लेकिन अंततः दिल्ली में झुग्गियों का विध्वंस जैसी कई घटनाओं को आपातकाल के समर्थन में अंजाम दिया गया।

कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस गलती को स्वीकार नहीं किया

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस गलती को स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि राजीव गांधी ने भी कभी इसे गलत नहीं माना। राजीव गांधी ने दंगों को जस्टिफाई करने की मानसिकता भी दिखाई। जब उन्होंने कहा, 'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है।' इस पूरी स्थिति में सबसे दुखद बात यह रही कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस की अर्जियों को खारिज करने के लिए भी संविधान में बदलाव कर दिए गए। श्री जयप्रकाश नारायण उस समय के एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने उत्पन्न हो रहे खतरे को न केवल पहचाना, बल्कि उसका गंभीर मूल्यांकन भी किया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, उन्होंने एक ऐतिहासिक वाक्य कहा 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि।' बाद में इंदिरा गांधी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने यह भी लिखा, "एक गलत फैसले को सही ठहराने के लिए आप बार-बार गलत निर्णय ले रही हैं। इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा।" लोकनायक जयप्रकाश नारायण उस समय समूचे देश की आवाज बन गए। उन्हीं की आवाज ने भारत को दोबारा लोकतंत्र लौटाया। करोड़ों भारतीयों ने आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ता, जनसंघ और कांग्रेस के असंतुष्ट नेता, सर्वोदय आंदोलन के अनुयायी, गांधीवादी चिंतक, हर वर्ग के लोग जेलों में बंद हुए, सत्याग्रह किया और बिना डरे, बिना थके, लगातार संघर्ष करते रहे। जनता भी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ इन संघर्षशील जनों के साथ खड़ी रही।

लोकतंत्र में जनता निर्णायक

श्री शाह ने कहा कि जन प्रबोधन अर्थात् जनता के मन में लोकतांत्रिक विचारों को गहराई से स्थापित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान की आत्मा की रक्षा केवल संसद या न्यायपालिका के भरोसे नहीं की जा सकती। संविधान की आत्मा की रक्षा देश की जनता की सामूहिक जिम्मेदारी है। जो भी संविधान के मूल स्वरूप और भावना के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे दंडित करने की जिम्मेदारी जनता पर ही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णायक होती है। आज का दिन उसी स्मृति का दिन है। कल 'संविधान हत्या दिवस' है और इस दिन को देशभर में मनाकर हम आने वाली पीढ़ियों युवाओं और किशोरों को यह लोकतांत्रिक संस्कार सौंप सकते हैं। यह संस्कार अगले 50 वर्षों तक राष्ट्र की चेतना को दिशा देगा और यही हमारा कर्तव्य है। ■

आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए नरेन्द्र मोदी का संघर्ष

25 जून, 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल 21 महीने का अंधकारमय काल था, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं को छीन लिया गया, सामूहिक गिरफ्तारियां हुईं, सेंसरशिप और राज्य प्रायोजित अधिनायकवाद का बोलबाला था।

- चुनावी कदाचार के लिए इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आपातकाल लगाया गया, बढ़ते हुए जनाक्रोश को दबाया जा सके। इस दौरान सरकार का पूरा ध्यान जेपी के नेतृत्व वाली संपूर्ण क्रांति एवं गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन जैसे आंदोलनों को दबाने पर था।
- 1,00,000 से अधिक लोगों— राजनीतिक विरोधी, पत्रकार, छात्र नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल भेजा गया; 4 जुलाई, 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके कार्यकर्ता भूमिगत हो गए।

नरेन्द्र मोदी का उदय

- मात्र 25 वर्ष की आयु में श्री नरेन्द्र मोदी एक आरएसएस प्रचारक के तौर पर गुजरात में कार्य कर रहे थे, जहां उन्हें संगठन को भूमिगत रूप से जीवित रखने का कार्यभार सौंपा गया था।
- उन्होंने गुजरात के प्रमुख आरएसएस नेताओं, जैसे— लक्ष्मणराव इनामदार (वकील साहब), केशवराव देशमुख और वसंत गजेंद्रगड़कर के साथ काम किया और नानाजी देशमुख एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी के साथ समन्वय में रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक संघर्ष समिति का नेतृत्व किया।

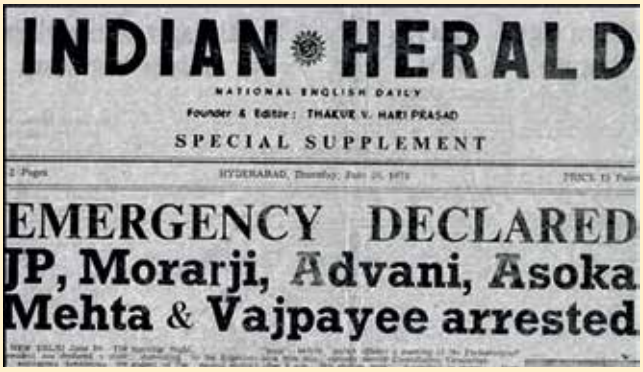

INDIAN HERALD

NATIONAL ENGLISH DAILY

Founder & Editor: THAKUR V. HARI PRASAD

SPECIAL SUPPLEMENT

EMERGENCY DECLARED

JP, Morarji, Advani, Asoka Mehta & Vajpayee arrested

भेष बदलने में माहिर: मोदी के भूमिगत अवतार

- श्री मोदी आपातकाल के दौरान पुलिस को लगातार चकमा देते रहे, जबकि गुजरात पुलिस बहुत सतर्क थी।
- उन्होंने कई तरह के भेष धारण किए: एक साधु, एक सरदारजी, एक अगरबत्ती विक्रेता और यहां तक कि एक बुजुर्ग सिख जो पगड़ी पहने हुए था, ताकि बिना किसी की नजर पड़े वे जिलों में घूम सकें।
- एक बार उन्होंने मुंबई के एक मिशन के दौरान भावी भाजपा नेता मकरंद देसाई के बेटे के रूप में अपनी पहचान बतायी— यह एक ऐसी योजना थी, जिसे उन्होंने निगरानी से बचने के लिए स्वयं ही तैयार किया था।

गुप्त संप्रेषक एवं मोबिलाइजर

- श्री मोदी ने साइक्लोस्टाइल मशीनों का उपयोग करके आपातकाल विरोधी साहित्य, विशेष रूप से आरएसएस के भूमिगत प्रकाशनों को प्रकाशित किया, इस दौरान अनुवाद एवं राष्ट्रव्यापी वितरण की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर थी।
- उन्होंने कोड सिस्टम का बीड़ा उठाया, जैसे:
  - ✦ फोन नंबरों में अंकों की अदला-बदली
  - ✦ बैठकों को धार्मिक समारोहों के रूप में प्रस्तुत करना— जैसे सत्यनारायण पूजा
  - ✦ चंदन कार्यक्रम— गुप्त आरएसएस बैठकों के लिए एक कोड वाक्यांश
- उन्होंने स्वयंसेवकों को सलाह दी कि वे पुलिस से बचने के लिए

बैठक स्थल के बाहर अपनी चप्पलें बिखेर दें।

प्रतिरोध और गुप्त नेटवर्क

- श्री मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस, दत्तोपंत ठेंगड़ी और वी.एम. तारकुंडे जैसे प्रमुख नेताओं, जो आपातकाल का विरोध कर रहे थे, की गुजरात यात्राओं को समर्थन दिया।
- उन्होंने निम्नलिखित की देखरेख की:
  - ✦ विभिन्न भागने के रास्तों के साथ सुरक्षित घरों में गुप्त बैठकें।
  - ✦ गुजरात में ढोलका, मेहसाणा, जामनगर, पालनपुर और राजकोट के सत्याग्रह— जिसमें सैकड़ों लोगों ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी।
- उन्होंने सुनिश्चित किया कि आंदोलन विकेंद्रीकृत रहे, जिससे प्रत्येक जिला और स्वयंसेवक स्वतंत्र रूप से काम करें, लेकिन वे गुप्त चैनलों के माध्यम से जुड़े रहें।

जमीनी-स्तर पर विरोध-प्रदर्शन की रणनीति में नवप्रवर्तक

- श्री मोदी ने छात्रों को 'जेपी को रिहा करो' और 'आपातकाल हटाओ' जैसे नारे के लिए स्टील फ्रेम का उपयोग करके भित्तिचित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पुलिस के प्रतिक्रिया करने से पहले त्वरित निष्पादन संभव हो सके।
- उन्होंने बच्चों को फाइलें और संदेश पहुंचाने के लिए संदेशवाहक के रूप में नियुक्त किया— यह मानते हुए कि वे संदेह के घेरे में नहीं आयेंगे।

नैतिक एंकर और युवा प्रेरक

- पोरबंदर में जब सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और युवा स्वयंसेवक हतोत्साहित महसूस कर रहे थे, तो श्री मोदी ने उससे कहा;
  "भले ही आप अकेले हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की मंशा सही है तो एक व्यक्ति ही काफी है। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए।"
- उन्होंने मेडिकल छात्रों के साथ प्रेरक सत्र आयोजित किए और उन्हें पैम्फलेट वितरण के लिए अपनी गतिशीलता का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

जेल में बंद स्वयंसेवकों के परिवारों की सहायता

- श्री मोदी ने निम्नलिखित की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली:
  - ✦ जेल में बंद स्वयंसेवकों के परिवारों को वित्तीय सहायता और भोजन उपलब्ध कराना।
  - ✦ उनका उपचार और भावनात्मक सहयोग।
  - ✦ यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस न करे और संघ के स्वयंसेवकों का मनोबल ऊंचा बना रहे।

वरिष्ठ नेताओं और वैश्विक प्रेस का समर्थन

- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आपातकाल विरोधी संघर्ष का दस्तावेजीकरण करते हुए 'संघर्ष मा गुजरात' नामक पुस्तक लिखी। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जे. पटेल ने इसकी प्रशंसा की।
- द इकोनॉमिस्ट, द् न्यू यॉर्क टाइम्स और द् गार्जियन जैसे विदेशी मीडिया घरानों ने आरएसएस के अनूठे और संगठित प्रतिरोध को स्वीकार किया, विशेष रूप से गुजरात को एक प्रमुख केंद्र के रूप में मान्यता मिली।

आपातकाल की विरासत और सबक

- श्री मोदी के आपातकाल के अनुभवों ने निम्नलिखित को गहराई से प्रभावित किया:
  - ✦ लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता
  - ✦ उनकी संगठनात्मक शैली और संकट प्रबंधन क्षमताएं
  - ✦ नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और सत्तावादी प्रवृत्तियों को उजागर करने का उनका संकल्प।
- प्रधानमंत्री के तौर पर वे अक्सर आपातकाल को चेतावनी के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, वह इसे लोकतांत्रिक सतर्कता के लिए एक वैचारिक कसौटी के तौर पर भी संदर्भित करते हैं।

आपातकाल वह अग्निपरीक्षा थी, जिसने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की भावना को गढ़ा। नेपथ्य में रहकर लेकिन अडिग संकल्प के साथ काम करते हुए उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की धड़कन को मूर्त रूप दिया।

जब अन्य लोग शांत हो गए, तब उन्होंने रणनीति बनाई। जब अन्य लोगों के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तब उन्होंने प्रतिरोध के नेटवर्क को मजबूत किया।

प्रचारक से प्रधानमंत्री तक का उनका सफर सिर्फ राजनीतिक नहीं है— यह कहानी है कि कैसे भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संकट ने इसके सबसे प्रिय नेताओं में से एक को आकार दिया। ■

मई, 2025 में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई 6 साल में सबसे कम 2.82% हुई

मई, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर, 2021 के बाद सबसे कम है

भारत में खुदरा महंगाई यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मई, 2025 में गिरकर 2.82 प्रतिशत पर हो गई, जो फरवरी, 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 12 जून को मई, 2025 माह के लिए ग्रामीण, शहरी और दोनों के संयुक्त के लिए आधार 2012=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं जारी कीं, जिसकी मुख्य बातें निम्न हैं:

1. **हेडलाइन मुद्रास्फीति** (किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति का माप जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं): मई, 2025 के महीने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर मई, 2024 की तुलना में 2.82 प्रतिशत (अनंतिम) है। अप्रैल, 2025 की तुलना में मई, 2025 की हेडलाइन मुद्रास्फीति में 34 आधार अंकों की गिरावट है। यह फरवरी, 2019 के बाद सबसे कम वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति है।
2. **खाद्य मुद्रास्फीति:** मई, 2025 के महीने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर मई, 2024 की तुलना में 0.99 प्रतिशत (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसकी मुद्रास्फीति दर क्रमशः 0.95 प्रतिशत और 0.96 प्रतिशत है। अप्रैल, 2025 की तुलना में मई, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति में 79 आधार अंकों की तीव्र गिरावट देखी गई है। मई, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर, 2021 के बाद सबसे कम है। मई, 2025 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट मुख्य रूप से दालों और उत्पादों, सब्जियों, फलों, अनाज और उत्पादों, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, चीनी और मिष्ठान्न और अंडे की मुद्रास्फीति में गिरावट और अनुकूल आधार प्रभाव के कारण है।
3. **ग्रामीण मुद्रास्फीति:** मई, 2025 में ग्रामीण क्षेत्र में हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। मई, 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 2.59 प्रतिशत (अनंतिम) है, जबकि अप्रैल, 2025 में यह 2.92 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र में सीएफपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल, 2025 में 1.85 प्रतिशत की तुलना में मई, 2025 में 0.95 प्रतिशत (अनंतिम) रही।
4. **शहरी मुद्रास्फीति:** शहरी क्षेत्र की मुद्रास्फीति में अप्रैल, 2025 के 3.36 प्रतिशत से मई, 2025 में 3.07 प्रतिशत (अनंतिम) तक की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। खाद्य मुद्रास्फीति में भी अप्रैल, 2025 के 1.64 प्रतिशत से मई, 2025 में 0.96 प्रतिशत (अनंतिम) तक की तीव्र गिरावट देखी गई है।

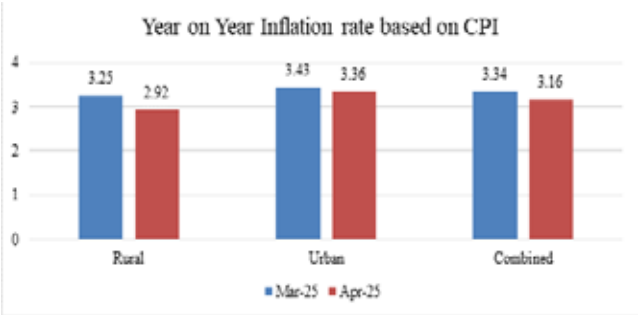

5. **आवास मुद्रास्फीति:** मई, 2025 के महीने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आवास मुद्रास्फीति दर 3.16 प्रतिशत (अनंतिम) है। अप्रैल, 2025 के महीने के लिए इसकी मुद्रास्फीति दर 3.06 प्रतिशत थी। आवास सूचकांक केवल शहरी क्षेत्र के लिए संकलित किया गया है।
6. **शिक्षा मुद्रास्फीति:** मई, 2025 के महीने के लिए वर्ष-दर-वर्ष शिक्षा मुद्रास्फीति दर 4.12 प्रतिशत (अनंतिम) है। अप्रैल, 2025 के महीने के लिए इसकी मुद्रास्फीति दर 4.13 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त शिक्षा मुद्रास्फीति है।
7. **स्वास्थ्य मुद्रास्फीति:** मई, 2025 के महीने के लिए वर्ष-दर-वर्ष स्वास्थ्य मुद्रास्फीति दर 4.34 प्रतिशत (अनंतिम) है। अप्रैल, 2025 के महीने के लिए इसकी मुद्रास्फीति दर 4.25 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त स्वास्थ्य मुद्रास्फीति है।
8. **परिवहन एवं संचार:** मई, 2025 के महीने के लिए परिवहन एवं संचार मुद्रास्फीति दर वर्ष-दर-वर्ष 3.85 प्रतिशत (अनंतिम) है। अप्रैल, 2025 के महीने के लिए इसकी मुद्रास्फीति दर 3.67 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त मुद्रास्फीति दर है।
9. **ईंधन और प्रकाश:** मई, 2025 के महीने के लिए ईंधन और प्रकाश मुद्रास्फीति दर वर्ष-दर-वर्ष 2.78 प्रतिशत (अनंतिम) है। अप्रैल, 2025 के महीने के लिए इसकी मुद्रास्फीति दर 2.92 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त मुद्रास्फीति दर है। ■

यह अकल्पनीय है कि विजयभाई हमारे बीच नहीं हैं: प्रधानमंत्री

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री विजय रूपाणी का 12 जून, 2025 को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री रूपाणी एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-171 में सवार थे, जो अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2 अगस्त, 1956 को उनका जन्म रंगून (अब यांगून), बर्मा में हुआ था, लेकिन वहां राजनीतिक अशांति होने के कारण श्री रूपाणी और उनका परिवार राजकोट, गुजरात आ गए थे। उन्होंने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और उन्हें आपातकाल के दौरान जेल भी जाना पड़ा।

श्री रूपाणी लगातार आगे बढ़ते रहेः वह राजकोट के पार्षद् (1987) बने., महापौर (1996-97) बने, राज्यसभा सांसद (2006-12) रहे और गुजरात के कैबिनेट मंत्री (2014) के रूप में परिवहन, जल आपूर्ति, श्रम और रोजगार जैसे विभागों को संभाला। वे अगस्त, 2016 से सितंबर, 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अपने शांत स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले श्री रूपाणी ने गुजरात के शासन पर एक अमिट छाप छोड़ी है— कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के दौरान प्रदेश का नेतृत्व किया। उनके परिवार में उनकी पत्नी अंजलि, बेटा रुषभ और बेटी राधिका हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें 'विनम्र और मेहनती' कार्यकर्ता के रूप में याद किया तथा गुजरात के प्रति उनके समर्पण और सेवा की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने श्री विजयभाई रूपाणी के परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यह अकल्पनीय है कि विजयभाई हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। विजयभाई विनम्र और मेहनती थे तथा पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पूरी लगन से काम किया।"

प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में दुर्घटनास्थल का भी दौरा किया। उन्होंने 'एक्स' के जरिए बताया, "विनाश का दृश्य दुःखद है। अधिकारियों और टीमों ने घटना के बाद अथक परिश्रम किया। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है।"

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा, "अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। वे भाजपा संगठन के सच्चे सिपाही और कर्तव्यनिष्ठ जनसेवक थे। रूपाणी जी का निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। गुजरात के विकास और जनसेवा के क्षेत्र में उनके विचार और कार्य सदैव याद किये जाएंगे। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें।"

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, "गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी जी के साथ संगठन में लम्बे समय तक कार्य किया। चाहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन को सशक्त करना हो या मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की विकास यात्रा को गतिशील रखना हो, विजयभाई ने हर दायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि अब वे हम सबके बीच नहीं रहे। स्वभाव से शांत व विचारशील रूपाणी जी की संगठन के प्रति निष्ठा और अनुशासनप्रियता अद्भुत थी। कुछ दिनों पूर्व ही उनसे भेंट हुई और पंजाब में संगठन संबंधी जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजलि रूपाणी जी से बात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। दुःख की इस घड़ी में पूरा भाजपा परिवार उनके साथ खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।"

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने दिवंगत नेता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उन्हें मूल्यों, दूरदर्शिता और सेवाभाव वाले व्यक्ति के रूप में याद किया। ■

ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को समझना जरूरी है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जून को कनाडा स्थित कनानास्किस में जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लिया। यह कार्यक्रम जी-7 शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा था। उन्होंने 'ऊर्जा सुरक्षाः बदलती दुनिया में पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा' विषय पर एक सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री श्री मार्क कार्नी को उनके निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और जी-7 को अपनी यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भविष्य की पीढ़ियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता ऐसे सिद्धांत हैं जो ऊर्जा सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भले ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसने समय से पहले अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

एक टिकाऊ और हरित भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, मिशन लाइफ और वन सन-वन वर्ल्ड-वन ग्रिड जैसी कई वैश्विक पहल की हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उन्हें और मजबूत करने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अनिश्चितता और संघर्षों ने ग्लोबल साउथ के देशों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को विश्व मंच पर सुनाने को अपनी जिम्मेदारी समझता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक स्थायी भविष्य के बारे में गंभीर है तो दुनिया के लिए ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को समझना जरूरी है।

श्री मोदी ने आतंकवाद का समर्थन और उसे बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने आगे कहा कि आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए और आतंकवाद का समर्थन करने वालों को कभी भी पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी, एआई और ऊर्जा के बीच संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, लेकिन प्रौद्योगिकी में स्वयं ऊर्जा का व्यापक उपयोग होता है और स्वच्छ एवं हरित पहलों के माध्यम से इसे कैसे टिकाऊ बनाया जाए, इसकी रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है।

कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कनाडा के प्रधानमंत्री श्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के सम्मान और संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के आधार पर भारत-कनाडा संबंधों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने चिंताओं और संवेदनशीलताओं के लिए आपसी सम्मान, लोगों के बीच मजबूत संबंधों और बढ़ती आर्थिक पूरकताओं पर आधारित रचनात्मक और संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बारे में दोनों पक्ष संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए संतुलित व रचनात्मक कदम उठाने पर सहमत हुए और इसकी शुरुआत एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की शीघ्र वापसी से होगी।

दोनों नेताओं ने विश्वास बहाली और संबंधों में गति लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ मंत्रिस्तरीय और कार्य-स्तरीय संबंधों को फिर से शुरू करने के महत्व पर बल दिया। ■

भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15-16 जून, 2025 को साइप्रस की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह यात्रा पिछले दो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की, जो साइप्रस और भारत के बीच बढ़ते व्यापक सहयोग को दर्शाती है। उन्होंने आर्थिक, तकनीकी और जन-जन के बीच संबंधों में हाल की प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने शांति, लोकतंत्र, कानून के शासन, प्रभावी बहुपक्षवाद और सतत विकास के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की।

सुरक्षा, रक्षा और संकट के समय सहयोग

साइप्रस और भारत ने अंतरराष्ट्रीय और सीमापार आतंकवाद सहित सभी रूपों और प्रतिरूपों में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की मुक्त स्वर में निंदा की और शांति एवं स्थिरता को कमजोर करने वाले हाइब्रिड खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

साइप्रस ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति एकजुटता और अटूट समर्थन व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने हाल ही में भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमलों में नागरिकों की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

यूरोपीय संघ: भारत की रणनीतिक भागीदारी

2026 की शुरुआत में साइप्रस द्वारा यूरोपीय संघ की परिषद् की अध्यक्षता किए जाने की संभावना को देखते हुए दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। साइप्रस ने अध्यक्षता के दौरान यूरोपीय संघ और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। ■

कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में चार समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री आंद्रेज प्लेंकोविच से ज़गरेब में मुलाकात की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह क्रोएशिया की पहली यात्रा थी और इसलिए यह भारत-क्रोएशिया संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जगरेब हवाई अड्डे पर श्री मोदी का श्री प्लेंकोविच ने एक विशेष और गर्मजोशी भरे अंदाज में स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष, सांस्कृतिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और शिपिंग, डिजिटलीकरण, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मा और पर्यटन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर हैं।

नेताओं ने स्टार्ट-अप और नवाचार के क्षेत्र में साझेदारी की हाल में की गई पहलों पर ध्यान दिया। उन्होंने दोनों देशों में समावेशी और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक व्यापार-से-व्यापार सहयोग को प्रोत्साहित करने और निवेश साझेदारी और संयुक्त उद्यमों को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता को पहचाना। वे भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार के महत्व पर सहमत हुए। क्रोएशिया मध्य और दक्षिण-पूर्वी यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है।

प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को क्रोएशिया द्वारा दिए गए मजबूत समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री श्री प्लेनकोविक को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ के रणनीतिक संबंधों के गहराने पर संतोष व्यक्त किया और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

वार्ता के बाद कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में चार समझौता ज्ञापनों तथा हिंदी चेयर के नवीनीकरण पर हस्ताक्षर किए गए। ■

पिछले एक दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को हराया है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 जून को बिहार के सीवान में 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने सीवान को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरक भूमि बताया। उन्होंने कहा कि इस भूमि ने देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाया है और संविधान को मजबूत किया है।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में बिहार में लगभग 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं जबकि 1.5 करोड़ घरों को नल का जल मिला है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य भर में 45,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि अब बिहार के छोटे शहरों में नए स्टार्ट-अप उभर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में गरीबी उन्मूलन के नारे लंबे समय से सुने जा रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं की सरकार है जिसने यह साबित कर दिया कि गरीबी को कम किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा, "पिछले दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को मात दी है।" उन्होंने कहा कि विश्व बैंक जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं ने भारत की इस उपलब्धि की प्रशंसा की है।

श्री मोदी ने कहा कि बिहार और खासकर श्री नीतीश कुमार की सरकार ने इस राष्ट्रीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले बिहार की आधी से ज्यादा आबादी अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आती थी। हालांकि, पिछले दस सालों में बिहार में करीब चार करोड़ लोगों ने गरीबी को मात दी है। ■

'ओडिशा ने अपनी विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ विकास के मंत्र को पूरे दिल से अपनाया है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 जून को भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। ओडिशा के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने पेयजल, सिंचाई, कृषि अवसंरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना, ग्रामीण सड़कें और पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ भाग और एक नई रेल लाइन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी 18,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 20 जून एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि इस दिन ओडिशा की पहली भाजपा सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, "यह वर्षगांठ केवल एक सरकार की नहीं, बल्कि जनसेवा और जनविश्वास के लिए समर्पित सुशासन की स्थापना की है।" उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार ने ओडिशा के करोड़ों मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं।

ओडिशा में भाजपा सरकार का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर लोगों द्वारा भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की तैयारियों में लगे होने के शुभ संयोग को ध्यान में रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ न केवल पूजनीय हैं, बल्कि वे असीम प्रेरणा के स्रोत भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद अमरीका यात्रा के राष्ट्रपति के निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने आज ही भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि पर जाने की योजना बना ली थी। ■

हमने दिखाया है कि आतंक को कैसे हराया जा सकता है

राजनाथ सिंह

आतंकवाद मानवता के लिए एक अभिशाप है। यह क्रांति, शहादत और हिंसा जैसे भ्रामक दृष्टिकोण की धारणाओं पर पनपता है। ऐसा दावा कि 'एक आतंकवादी, किसी दूसरे के लिए स्वतंत्रता सेनानी है' एक खतरनाक मिथ्या तर्क है। वास्तविकता में स्वतंत्रता कभी भी भय एवं रक्तपात कर हासिल नहीं की जा सकती।

आतंकवाद की पूरी अवधारणा 'भय' पर आधारित है। लेकिन, भय फैलाने के बावजूद, वे निराशावाद की भावना पैदा करने में विफल रहे हैं। भारत इस तथ्य का प्रमाण है। चाहे वह 26/11 हो या 2001 का संसद हमला या हाल ही में हुआ पहलगाम हमला, भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत और दृढ़ हुआ है। सभी शांतिप्रिय देशों को इस खतरे को हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है।

भारत ने दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। दशकों से हम पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहे हैं। हाल ही में पहलगाम में हुआ हमला भारतीय एकता को तोड़ने का एक क्रूर और असफल प्रयास था। यह इस बात से स्पष्ट भी है कि आतंकवादियों ने कैसे पर्यटकों की हत्या करने से पहले उनके धर्म के बारे में पूछा। भारतीय एकता को खतरे में डालने का एक ऐसा ही प्रयास तब सामने आया जब पाकिस्तान ने विभिन्न धर्मों से जुड़े धार्मिक स्थलों पर ड्रोन और तोपखाने से हमला किया। कोई भी धर्म ऐसे कायरतापूर्ण कृत्यों को मंजूरी नहीं दे सकता। आतंकवादी अपनी बर्बरता को सही ठहराने के लिए रणनीतिक रूप से धर्म का सहारा लेते हैं। धर्म का यह दुरुपयोग आकस्मिक या आवेगपूर्ण नहीं है; यह अत्याचारों को झूठी वैधता प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति है।

> आतंकवाद की पूरी अवधारणा 'भय' पर आधारित है। लेकिन, भय फैलाने के बावजूद, वे निराशावाद की भावना पैदा करने में विफल रहे हैं। भारत इस तथ्य का प्रमाण है। चाहे वह 26/11 हो या 2001 का संसद हमला या हाल ही में हुआ पहलगाम हमला, भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत और दृढ़ हुआ है। सभी शांतिप्रिय देशों को इस खतरे को हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है

भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के प्रति हमारी नीति शून्य-सहिष्णुता की है। वार्ता और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के साथ भविष्य में होने वाली कोई भी वार्ता केवल आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर केंद्रित होगी। साथ ही, अगर पाकिस्तान गंभीर है, तो उसे हाफिज सईद एवं मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों को सौंपना होगा।

हम लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं और एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण तथा रणनीति की तलाश करते रहे हैं। हमारे सशस्त्र बलों को पहले केवल रक्षात्मक कार्रवाई करने की अनुमति थी। सर्जिकल स्ट्राइक (2016), बालाकोट स्ट्राइक (2019) और अब ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के प्रति अपनी नीति को पुनःपरिभाषित किया है।

अब हमारी नीति है कि हम आतंकवादियों को सक्रिय रूप से खत्म करेंगे, चाहे वे कहीं भी हों। अब किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है, तो राष्ट्र और आतंकवादियों के बीच कोई अंतर किए बिना मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान अपनी धरती से सक्रिय आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगा पाता है, तो उसे इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।

नई दिल्ली में आतंकवाद के वित्तपोषण पर तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "हम मानते हैं कि एक भी हमला बहुत अधिक होता है और एक भी जान गंवाना बहुत अधिक दुःखदायी है। इसलिए, हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ से उखाड़ नहीं दिया जाता।" ऑपरेशन सिंदूर से भारत सरकार एवं सशस्त्र बलों ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बहुत ही सधे हुए ऑपरेशन के साथ हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया। हम जानते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई

आवश्यक है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। वह आतंकवादी ढांचे की नींव है जिसे नष्ट करने की आवश्यकता है। चूंकि पाकिस्तान आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, इसलिए भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक एवं आर्थिक रूप से सफलतापूर्वक अलग-थलग कर दिया है। हमने सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय रूप से रोक नहीं देता। यह निर्णय पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी 16 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 80 प्रतिशत और अपने कुल जल उपयोग के 93 प्रतिशत के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, जो 237 मिलियन लोगों का भरण-पोषण करती है और पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में एक-चौथाई का योगदान देती है।

आतंकवाद सिर्फ़ भारत की समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है। आतंकवादी नेटवर्क को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए हमें छोटे-छोटे प्रयासों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसमें पांच मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं—

सबसे पहले, 'आतंकवाद' शब्द को परिभाषित करना होगा। आतंकवाद क्या है, इस पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। हम आतंकवाद को परिभाषित करने के सबसे करीब संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ व्यापक सम्मेलन के दौरान आए थे, जो एक भारतीय प्रस्ताव पर आधारित है। इस लड़ाई को केवल आर्थिक संबंधी मुद्दों तक सीमित नहीं रखना जाना चाहिए, हमें आतंकवादी कृत्यों की जांच या मुकदमा चलाने और विदेश से आतंकवादियों के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा की आवश्यकता है।

दूसरा, हमें न केवल आतंकवादी संगठनों बल्कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों के वित्त पर भी रोक लगानी होगी। बहुपक्षीय एजेंसियों और दानदाता देशों को यह पहचानना होगा कि पाकिस्तान का इतिहास अपने बेलआउट पैकेजों का दुरुपयोग करने का रहा है और वह सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए अपने ऋण का उपयोग करता आया है। इसलिए, पाकिस्तान को एफएटीई द्वारा फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाना चाहिए और जब तक इस्लामाबाद विश्वसनीय रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना बंद नहीं कर देता, तब तक उसकी सभी फंडिंग बंद कर दी जानी चाहिए।

तीसरा, एक बात जो लंबे समय से जानी जाती थी, लेकिन अब यह और भी स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान में सरकार और नॉन स्टेट एक्टर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह हाल ही में तब स्पष्ट हुआ जब नामित आतंकवादियों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और उसमें वर्दीधारी सैन्य अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान में इस बात का लगातार खतरा बना हुआ है कि परमाणु हथियार नॉन स्टेट एक्टर के हाथ लग सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस गंभीर जोखिम को स्वीकार करना चाहिए और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखा जाना चाहिए।

चौथा, उन देशों की पहचान करने की आवश्यकता है जो अपने पड़ोस राष्ट्रों को अस्थिर करने के लिए कार्य करते हैं। आतंकवादी कृत्यों पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर नहीं हो सकती कि वे कहां हुए हैं या पीड़ितों की राष्ट्रीयता क्या है। जब राष्ट्र अपनी सुविधा के अनुसार आतंकवादी घटनाओं की निंदा करने के विकल्प को चुनते हैं, तो यह हमारी सामूहिक प्रतिक्रिया को कमज़ोर करता है और अपराधियों को बढ़ावा देता है।

पांचवां, पाकिस्तान में आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने दुनिया भर के लिए एक बड़ा खतरा हैं क्योंकि उनकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच है और अब वे एआई, स्वायत्त प्रणालियों, संवर्धित वास्तविकता, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं। यही कारण है कि इस खतरे से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। अब समय आ गया है कि सभी देश एक साथ आएं और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़े हों।

इस तरह की संधि की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 9/11 हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था, "हमें आतंकवाद के समर्थन में दिये जाने वाले किसी भी वैचारिक, राजनीतिक या धार्मिक विचार का दृढ़ता से खंडन करना चाहिए।" उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "अब से, प्रत्येक देश जो केवल अपनी सुरक्षा की चिंता करते है, उन्हें पूरे विश्व के कल्याण पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा।" भारत आतंकवाद को उसके सभी रूपों में समाप्त करने के कृतसंकल्पित है। हम सभी शांतिप्रिय देशों से आग्रह करते हैं कि वे हमारे साथ जुड़ें।

(लेखक भारत के रक्षा मंत्री हैं)

सपनों से हकीकत तक

अश्विनी वैष्णव

एक 'नया भारत' आकार ले रहा है - जहां प्रगति को केवल जीडीपी से नहीं, बल्कि सम्मान एवं अवसरों से मापा जाता है। कडप्पा की एक गृहिणी अन्नम लक्ष्मी भवानी ने एक सफल जूट बैग निर्माण इकाई शुरू करने के लिए मुद्रा ऋण लिया। हरियाणा के जगदेव सिंह अपनी फसलों से संबंधित निर्णय अब एआई ऐप का उपयोग करके लेते हैं और मीरा मांझी को उज्ज्वला के तहत एलपीजी कनेक्शन मिला है, जिससे उनकी रसोई धुआं रहित हुई है और वे अपने बच्चों के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाती हैं। ये भारत भर के गांवों, कस्बों और शहरों की रोजमर्रा की वास्तविकताएं हैं। ये परिवर्तन ऐसे सुधारों और एक ऐसे नेतृत्व के परिणामस्वरूप आये हैं जो अंतिम नागरिक को सशक्त बनाने में विश्वास करता है।

हमारा मार्गदर्शक दर्शन अंत्योदय रहा है – जो अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निर्देशित यह विजन चार सरल लेकिन शक्तिशाली स्तंभों पर आधारित है— जैसे ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण जो जोड़ता हो, ऐसा विकास जो समावेशी हो, ऐसा विनिर्माण जो रोजगार पैदा करे और ऐसी व्यवस्थाओं जो सशक्त बनाए।

पिछले 11 वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सार्वजनिक निवेश में यह उछाल भारत के बुनियादी ढांचे - भौतिक, डिजिटल और सामाजिक में सबसे अधिक दिखाई देता है। पिछले 11 वर्षों में लगभग 59,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाए गए हैं और 37,500 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। हाल ही में चेनाब और अंजी पुलों का उद्घाटन किया गया – जो एक आधुनिक भारत का प्रतीक है। कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन का आना यहां के निवासियों के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं हैं।

> **पिछले 11 वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सार्वजनिक निवेश में यह उछाल भारत के बुनियादी ढांचे— भौतिक, डिजिटल और सामाजिक में सबसे अधिक दिखाई देता है। पिछले 11 वर्षों में लगभग 59,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाए गए हैं और 37,500 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं**

कनेक्टिविटी की यह भावना रेलवे से आगे बढ़कर अब डिजिटल हाईवे तक पहुंच गई है। भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (डीपीआई) वैश्विक बेंचमार्क बन गया है। यूपीआई, आधार और डिजिलॉकर का अब वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। हर दिन 141 करोड़ से ज़्यादा आधार सत्यापन और 60 करोड़ यूपीआई लेन-देन इसकी पहुंच को दर्शाते हैं। इसके पीछे का विचार सरल है: तकनीक का लोकतंत्रीकरण।

यही दृष्टिकोण इंडियाएआई मिशन को आगे बढ़ाता है। 34,000 से ज़्यादा हाई-स्पीड कंप्यूटर चिप्स, जिन्हें जीपीयूएस के नाम से जाना जाता है, अब सभी के लिए वैश्विक लागत के सिर्फ़ एक-तिहाई पर उपलब्ध हैं। एआई विकास के लिए इन चिप्स की जरूरत होती है। इसे और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, ऐकोशा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया गया है जो सीखने एवं नवाचार के लिए 370 से ज़्यादा डेटासेट और 200 एआई मॉडल की पेशकश करता है।

हमारा फोकस तकनीक के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सेवाओं पर भी है। पिछले 11 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 हो गई है और एम्स संस्थानों की संख्या सात से बढ़कर 23 हो गई है। एमबीबीएस और पीजी सीटें भी दोगुनी से ज्यादा हो गई हैं। 530 मिलियन से अधिक जन-धन खाते खोले गए हैं— जो यूरोप की आबादी से भी ज्यादा है। 40 मिलियन घर बनाए गए हैं, 120 मिलियन शौचालयों का निर्माण किया गया है और 100 मिलियन परिवार अब स्वच्छ एलपीजी से खाना बनाते हैं। 'हर घर जल' के तहत 140 मिलियन घरों में नल के कनेक्शन भी पहुंच गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा 350 मिलियन लोगों को कवर करता है और 110 मिलियन किसान अब पीएम-किसान के माध्यम से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करते हैं। यह यात्रा मीरा मांझी जैसे लोगों की कहानियों के माध्यम से जीवंत हो जाती है, जो उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी है, अब उनके घर में नल का पानी, हर महीने मुफ़्त राशन और उज्ज्वला योजना के तहत धुआं रहित रसोई है। यह समावेशी विकास का ऐसा आयाम है जो हमारे हाल के इतिहास में नहीं देखा गया।

2015 में हमने रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को पुनर्जीवित करने के

लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की। आज, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण छह गुना बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आठ गुना बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है और सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले सामानों में से एक बन गया है। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक है। हम अब नई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उत्पादन करके विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को और मजबूत कर रहे हैं।

इसके साथ, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन अब ब्लूप्रिंट से सफलता की ओर बढ़ रहा है। देश की पहली वाणिज्यिक प्रयोगशाला निर्माणाधीन है; पांच ओएसएटी इकाइयां चल रही हैं; भारत के छात्रों और इंजीनियरों ने स्वदेशी आईपी से चलने वाले 20 से अधिक चिपसेट डिजाइन किए हैं। हमने 270 विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय ईडीए उपकरणों से जोड़ा है। यह सेमीकंडक्टर प्रतिभा पाइपलाइन की नींव है जिस पर दुनिया भरोसा कर सकती है।

पिछले दशक में शासन में कुछ क्रांतिकारी बदलाव हुए है। 1,500 से ज़्यादा पुराने कानून निरस्त किए गए और 40,000 से ज़्यादा अनुपालन समाप्त किए गए। दूरसंचार अधिनियम और डीपीडीपी अधिनियम जैसे नए कानून बनाए गए है, जो विश्वास और सरलता पर आधारित हैं। इसने निवेश, नवाचार और औपचारिकता को बढ़ावा दिया है, जिससे एक बेहतर माहौल का निर्माण हुआ है।

आतंकवाद के प्रति भारत का दृष्टिकोण भी बदला है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर तक, भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में स्पष्टता और साहस दिखाया है। हर जवाब में एक तेज, निर्णायक कार्रवाई दिखाई देती है – और वह भी हमारी अपनी शर्तों पर। आतंकी हमलों का जवाब देने का यह नया तरीका मोदी सिद्धांत का हिस्सा है। यह तीन स्तंभों पर आधारित है। भारत की शर्तों पर निर्णायक जवाबी कार्रवाई, परमाणु ब्लैकमेल के लिए शून्य सहिष्णुता, और आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं। इस बार हमारी प्रतिक्रिया में स्वदेशी तकनीकों और क्षमताओं का उपयोग किया गया। विकसित बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र को न केवल अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भरता के साथ ऐसा करना चाहिए— और भारत ने ठीक यही किया।

पिछले दशक में शासन में कुछ क्रांतिकारी बदलाव हुए है। 1,500 से ज़्यादा पुराने कानून निरस्त किए गए और 40,000 से ज़्यादा अनुपालन समाप्त किए गए। दूरसंचार अधिनियम और डीपीडीपी अधिनियम जैसे नए कानून बनाए गए है, जो विश्वास और सरलता पर आधारित हैं। इसने निवेश, नवाचार और औपचारिकता को बढ़ावा दिया है, जिससे एक बेहतर माहौल का निर्माण हुआ है

2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के अंत में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2004 से 2014 के बीच भारत 11वें स्थान पर ही रहा। लेकिन पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री मोदी की सुधारवादी नीतियों के कारण भारत के विकास ने फिर से गति पकड़ी है। आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में समावेशी विकास के इन 11 वर्षों ने लोगों को सब्सिडी या सेवाओं से कहीं ज़्यादा दिया है। उनमें एक विश्वास पैदा किया है और बेहतर भविष्य में दृढ़ विश्वास ही राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। ■

(लेखक केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं)

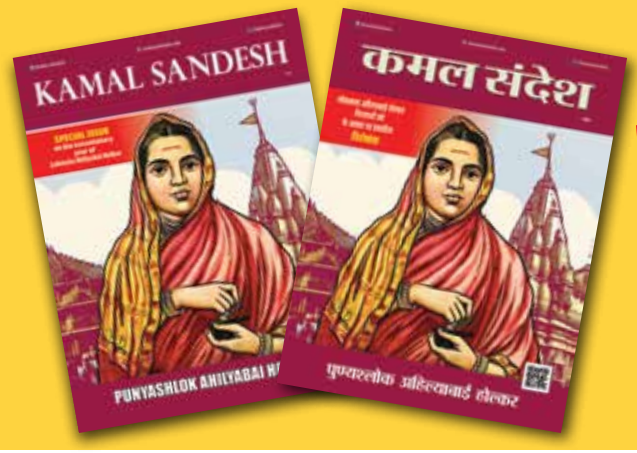

कमल संदेश विशेषांक

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

श्रम शक्ति को सशक्त बनाने और भविष्योन्मुख भारत के 11 वर्ष

डॉ. मनसुख मंडाविया

भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएगा, इसलिए रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को हमारे विकसित भारत मिशन के मूल में रखा गया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का कार्यबल नीति, नियोजन और प्रगति के केंद्र में रहा है। इस बदलाव के कारण रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में ऐतिहासिक सुधार हुआ है।

2014 में भारत का रोजगार परिदृश्य बेहद कमजोर था, सामाजिक सुरक्षा कवरेज सीमित थी और अधिकांश श्रमिक, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कल्याणकारी योजनाओं के सुरक्षात्मक दायरे से बाहर थे। इस चुनौती को पहचानते हुए मोदी सरकार ने साहसिक और संरचनात्मक सुधार किए।

मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी प्रमुख पहलों और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास अभियान ने रोजगार सृजन के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा किये। आरबीई केएलईएमएस के अनुसार 2004-2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं। इसकी तुलना में 2014-2024 के बीच 17 करोड़ से अधिक नौकरियां के अवसर मिले। पीएलएफएस के अनुसार, रोजगार दर (डब्लूपीआर) 2017-18 में 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 58.2 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर (यूआर) 6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई। इतना ही नहीं, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी काफी प्रगति हुई है, ईपीएफओ के अनुसार पिछले सात वर्षों में 7.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां के अवसर आये हैं।

> आरबीई केएलईएमएस के अनुसार 2004-2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं। इसकी तुलना में 2014-2024 के बीच 17 करोड़ से अधिक नौकरियां के अवसर मिले। पीएलएफएस के अनुसार, रोजगार दर (डब्लूपीआर) 2017-18 में 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 58.2 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर (यूआर) 6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई

युवा और नारी शक्ति का सशक्तीकरण

भारत की विकास यात्रा के केंद्र में युवा और नारी सशक्तीकरण है। इसके प्रमाण के रूप में महिला रोजगार दर (डब्लूपीआर) 2017-18 में 22 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 40.3 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई। यह बदलाव ग्रामीण भारत में और भी महत्वपूर्ण रहा है, जहां महिला रोजगार में 96 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये परिणाम पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए परिवर्तनकारी सुधारों और केंद्रित पहलों का परिणाम हैं। आज, 15 मंत्रालयों में 70 से अधिक केंद्र प्रायोजित योजनाएं महिला उद्यमिता का समर्थन करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं।

भारत में युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी 2013 के सिर्फ 33 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में लगभग 55 प्रतिशत हो गई है। यह प्रगति मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का परिणाम है। राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल जैसे प्लेटफ़ॉर्म रोजगार संबंधी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में उभरे हैं। 2015 में लॉन्च किए गए एनसीएस ने अब तक 5.5 करोड़ से अधिक नौकरी चाहने वालों को 46 लाख नियोक्ताओं से जोड़ा है, जिससे 5 करोड़ से अधिक नौकरी के अवसर पैदा हुए। नतीजतन, युवा रोजगार दर (डब्लूपीआर) 2017-18 में 31.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि में युवा बेरोजगारी 17.8 प्रतिशत से घटकर 10.2 प्रतिशत हो गई।

असंगठित कार्यबल को मान्यता

पिछले 11 वर्षों की सबसे परिवर्तनकारी उपलब्धियों में से एक भारत के विशाल असंगठित कार्यबल को मान्यता देना है।

2021 में मोदी सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस 'ई-श्रम पोर्टल' लॉन्च किया। केवल 4 वर्षों में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों सहित 30.8 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ चुके हैं। यह गतिशील पोर्टल वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है, जो श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ता है। वर्तमान में 13 से अधिक केंद्र सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाएं ई-श्रम के साथ एकीकृत हैं, जो निर्बाध एकल साइन-ऑन और बहुभाषी पहुंच प्रदान करती हैं। यह केवल तकनीकी प्रगति नहीं है, यह एक ऐसा शासन मॉडल है जो श्रमिक को सबसे पहले रखता है।

इसके अलावा, हम गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था के दायरे में लाए है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में उन्हें ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत करने और आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना के तहत विस्तारित स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करने की एक बड़ी घोषणा शामिल थी। इसके साथ मोदी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस उभरते कार्यबल को पर्याप्त सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच मिले।

ईएसआईसी और ईपीएफओ में सुधार

पिछले 11 वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जो लंबे समय से लालफीताशाही से ग्रस्त थी। इन सुधारों ने न केवल अभूतपूर्व पारदर्शिता स्थापित की है, बल्कि सिस्टम में अधिक दक्षता भी आयी है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), आधार एकीकरण, सरलीकृत ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र जैसी पहलों ने सेवा वितरण को सुलभ बनाया है और हमारे कार्यबल के जीवन को आसान बना दिया है।

इसके परिणामस्वरूप ईपीएफओ की सदस्यता 2013-14 में 11.78 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 34.63 करोड़ हो गई है। इसी अवधि के दौरान पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या 7.96 लाख से बढ़कर 27.05 लाख हो गई। इसके अलावा 2024-25 में निपटाए गए दावों की संख्या 6 करोड़ से अधिक हो गई, जो ईपीएफओ के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक संख्या है।

2021 में मोदी सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस 'ई-श्रम पोर्टल' लॉन्च किया। केवल 4 वर्षों में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों सहित 30.8 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ चुके हैं। यह गतिशील पोर्टल वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है, जो श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ता है

इस बीच ईएसआईसी भी बड़े बदलावों का साक्षी बना है, जिसकी पहुंच 2013-14 के केवल 393 जिलों से बढ़कर अब लगभग 700 जिलों तक हो गयी है। 2013-14 और 2024-25 के बीच बीमित व्यक्तियों की संख्या 1.95 करोड़ से बढ़कर 4.09 करोड़ हो गई है। इसी अवधि के दौरान लाभार्थियों की संख्या भी दोगुनी हुई है, जो 7.89 करोड़ से बढ़कर 15.87 करोड़ हो गई है। आज, ईएसआईसी कीमोथेरेपी, रोबोटिक सर्जरी और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, जिससे श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार

मोदी सरकार के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है। आज, 94 करोड़ से अधिक नागरिक कम से कम एक सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत आते हैं, जिससे भारत लाभार्थी संख्या के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कल्याणकारी प्रणाली चलाने वाला राष्ट्र बन गया है। भारत का सामाजिक सुरक्षा मॉडल 'सबका साथ, सबका विकास' में हमारे विश्वास का प्रमाण है, जहां आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा एक साथ चलते हैं।

पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी श्रम शक्ति को सशक्त बनाने और एक विकसित भारत की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रोजगार सृजन को प्राथमिकता देकर, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करके, संस्थागत वितरण को मजबूत करके और डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर, सरकार ने श्रमिकों को विकास के एजेंडे के केंद्र में रखा है। जैसे-जैसे हम विकसित भारत के विजन को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं, भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा कार्यबल बनने की तैयारी कर रहा है, बल्कि सबसे कुशल, संरक्षित और सशक्त देशों में से एक बनने की भी तैयारी कर रहा है। ■

(लेखक भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं)

धारा 370 के बाद बदलता कश्मीर

शिवप्रकाश

ऑपरेशन सिन्दूर के बाद मिशन 'पाक बेनकाब' के लिए श्री संजय झा के नेतृत्व वाले इंडोनेशिया गए डेलीगेशन में सम्मिलित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि "कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना मोदी सरकार का सही कदम था।" उन्होंने कहा, "धारा 370 हटने से कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रगति एवं आर्थिक समृद्धि आयी है।" 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह निर्णय ऐतिहासिक, साहसिक, देश की एकात्मता को पुष्ट करने वाला एवं कश्मीर के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है।

प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कश्मीर महर्षि कश्यप एवं माता सती की भूमि है। सम्राट अशोक एवं कुषाण वंश के शासन काल में कश्मीर की भूमि पर बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है। सम्राट ललितादित्य के शासनकाल में कश्मीर का विस्तार हुआ एवं संस्कृत भाषा को भी सम्मान मिला। श्रीनगर के पास स्थित श्रीशंकराचार्य मंदिर आज भी जगद्गुरू शंकराचार्य जी की दिग्विजय का स्मरण कराता है। कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं के मतांतरण के कारण कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि हुई।

स्वतंत्रता के समय देश की अन्य रियासतों के समान ही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर रियासत का भारत के साथ विलय, विलयपत्र पर हस्ताक्षर करके किया था। शेख अब्दुल्ला के दबाव के कारण कश्मीर में धारा 370 लगाना प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी का एक अदूरदर्शी कदम था, जो देश की एकात्मता एवं अखंडता में विभेद उत्पन्न करता था। उस समय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी जैसे अनेक नेताओं ने प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के इस कदम का विरोध भी किया था। भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने "एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे" के उद्घोष के साथ देशव्यापी आंदोलन किया था। जिसमें 23 जून, 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका बलिदान भी हो गया। तभी से भारतीय जनसंघ तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी का घोषित लक्ष्य धारा 370 को हटाना रहा था। जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त, 2019 को पूर्ण किया।

> **धारा 370 हटने के उपरान्त सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को समर्पित केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण कश्मीरी लोगों को भी इसका लाभ मिलने लगा, जो अभी तक इससे वंचित थे। अब सभी भारतीय नागरिक कश्मीर में भूमि का क्रय कर सकते हैं। इसके कारण 500 संपत्तियों की रजिस्ट्री एवं 3.5 हजार करोड़ का रियल एस्टेट में (Real Estate) निवेश कश्मीर को प्राप्त हुआ। कश्मीर से बाहर कश्मीरी लड़कियों के विवाह करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित होने के नियम से मुक्ति, महिला सशक्तीकरण की दिशा में निर्णायक कदम है**

धारा 370 हटने के उपरान्त सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को समर्पित केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण कश्मीरी लोगों को भी इसका लाभ मिलने लगा, जो अभी तक इससे वंचित थे। अब सभी भारतीय नागरिक कश्मीर में भूमि का क्रय कर सकते हैं। इसके कारण 500 संपत्तियों की रजिस्ट्री एवं 3.5 हजार करोड़ का रियल एस्टेट में निवेश कश्मीर को प्राप्त हुआ। कश्मीर से बाहर कश्मीरी लड़कियों के विवाह करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित होने के नियम से मुक्ति, महिला सशक्तीकरण की दिशा में निर्णायक कदम है। पाक से विस्थापित 1.5 लाख परिवार जिसमें वाल्मीकि, अनुसूचित जाति, जनजाति शरणार्थी अधिक हैं, उनको भी नागरिक अधिकार प्राप्त हो गए है। 35 लाख लोगों को निवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) मिलें हैं। शिक्षण संबंधी कानून लागू होने के कारण 10 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त हुई है। गरीब एवं अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण की सुविधा भी प्राप्त हुई है। पिछड़े वर्ग में नयी जातियों का समावेश एवं कोटे में वृद्धि पिछड़े वर्ग के उत्थान में निर्णायक कदम सिद्ध हो रहा है।

औद्योगिक विकास के कारण 56,000 करोड़ का निवेश जिसके कारण लगभग 80,000 लोगों को रोजगार की उपलब्धि हुई है। 1200 से अधिक स्टार्टअप भी अब विकास एवं रोजगार की गाथा लिख रहे हैं। कारीगरों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद अब नए-नए क्षेत्रों में बाजार प्राप्त कर रहा है। 370 की समाप्ति के बाद 10,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार एवं निर्माण

कार्य हुआ है। जोजिला एवं चेनानी नाशरी सुरंगों द्वारा मार्ग की दूरी कम हुई है। जम्मू से श्रीनगर फोरलेन हाईवे विकास की गाथा लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चिनाब नदी पर चिर प्रतिक्षित जिस पुल का उद्घाटन किया वह इंजीनियरिंग का चमत्कार एवं दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। चिनाब पुल नदी तल से 359 मीटर ऊपर है, जो पेरिस के एफेल टॉवर से भी ऊंचा है। जिसकी प्रशंसा स्वयं मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने की है। आयुष्मान योजना में 13 लाख से अधिक लोगों ने अपना उपचार कराया है। अब कश्मीर में फॉर्मूला कार रेसिंग भी हो रही है। जम्मू-कश्मीर का पल्ली भारत का पहला 'कार्बन न्यूट्रल पंचायत' है।

370 हटने के बाद कश्मीर में आयी शांति के कारण पर्यटन में भारी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार 2019 के बाद 50% की वृद्धि पर्यटकों की संख्या में भी हुई है। संपूर्ण प्रदेश में यह संख्या ढ़ाई करोड़ लगभग है।

आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस के कारण आतंकी घटनाओं में भी निरंतर गिरावट आयी है। देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह ने संसद में बताया कि आतंकवादी घटनाओं में 92% की कमी आयी है। आतंकियों की नयी भर्ती में भी निरंतर गिरावट आ रही है। मां वैष्णो देवी एवं अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। 370 हटने के बाद हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 65% मतदान कश्मीर की खुशहाली का ही गवाह है। जिसमें 32,000 चुने हुए प्रतिनिधि अपनी ग्राम पंचायतों के विकास की गाथा लिख रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मां शारदा मंदिर में दीपावली एवं सरस्वती पूजन का आयोजन संपन्न हुआ जहां 70 वर्षों से पूजा ही नहीं हुई थी। माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने 23 मार्च, 2023 को इसे खुलवाया। खीर भवानी मंदिर में भी विधिवत पूजा प्रारंभ हुई।

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक स्थान लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी को कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 'भारत एकता यात्रा' का आयोजन करना पड़ा था। यह संकल्प पुलिस सुरक्षा में 26 जनवरी, 1992 को तिरंगा फहराकर पूर्ण हुआ था। डॉ. मुरली मनोहर जोशी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस संकल्प की पूर्ति में उनके महत्वपूर्ण सहयोगी थे। उसी लाल चौक में 370 समाप्ति के बाद तिरंगा शान के साथ फहरा रहा है। केवल लाल चौक ही नहीं कश्मीरी अपने घरों में भी तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक उत्सवों को शान के साथ मना रहे हैं। श्रीकृष्णजन्म स्मृति में आयोजित हिंदू धार्मिक उत्सव श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी उसी लाल चौक में हर्षोल्लास से मनाया गया है।

370 हटने के बाद कश्मीर में आयी शांति के कारण पर्यटन में भारी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार 2019 के बाद 50% की वृद्धि पर्यटकों की संख्या में भी हुई है। संपूर्ण प्रदेश में यह संख्या ढ़ाई करोड़ लगभग है। आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस के कारण आतंकी घटनाओं में भी निरंतर गिरावट आयी है। देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह ने संसद में बताया कि आतंकवादी घटनाओं में 92% की कमी आयी है। आतंकियों की नयी भर्ती में भी निरंतर गिरावट आ रही है

धारा 370 की समाप्ति का परिणाम हुआ कि जम्मू-कश्मीर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विरासत से विकास' की गाथा को लिख रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर के नागरिक कश्मीर की विकास यात्रा से प्रभावित होकर भारत के साथ जुड़ने को आतुर हैं। पहलगाम जैसी आतंकी घटनाएं विकास की इस यात्रा को रोकने का ही कुत्सित प्रयास है। भारतीय समाज सभी प्रकार के षड्यंत्रों को उत्तर देते हुए भारतीय एकता और अखंडता का भाव लेकर पुनः गौरव के साथ खड़ा होगा। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ऐसे ही प्रयास प्रत्येक भारतीय में यह भाव जगाने में सफल हुए हैं । ■

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) हैं

भारत सितारों पर पहुंचा और उनकी रोशनी को लेकर घर लौटा

डॉ. जितेन्द्र सिंह

केरल का एक शांत मछवारों का गांव 'थुंबा', यहां भारत की अंतरिक्ष यात्रा एक चर्च के प्रांगण से प्रक्षेपित रॉकेटों के साथ शुरू हुई थी और लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन देश इन ऊंचाइयों को छू लेगा, जहां आज हम पहुंचे हैं। वह शांत संकल्प का समय था, जब सितारों तक पहुंचने का सपना सीमित साधनों लेकिन असीम महत्वाकांक्षा के साथ पोषित किया गया था। आज, वह सपना एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में परिपक्व हो गया है और जब हम नरेन्द्र मोदी सरकार के ग्यारह साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अधिक साहसिक, समावेशी और आम नागरिकों के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस होता है। यह परिवर्तन केवल रॉकेट एवं उपग्रहों के बारे में नहीं है – यह लोगों जीवन के बारे में है। यह बताता है कि कैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चुपचाप हमारी दिनचर्या में प्रवेश कर गई है, जिसके परिणामस्वरूप दूरदराज के गांव के किसानों से लेकर डिजिटल कक्षा में छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अंतरिक्ष विभाग के रणनीतिक नेतृत्व में भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकास यात्रा में योगदान देने, नागरिकों के सशक्तीकरण एवं नये अवसरों के तौर पर पुनः परिभाषित किया है। 2014 से शुरू किए गए सुधारों ने नए आयाम खोले हैं। 2020 में IN-SPACe के निर्माण ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी, जिससे नवाचार की लहर उठी। आज, 300 से अधिक स्पेसटेक स्टार्टअप उपग्रह बना रहे हैं, लॉन्च वाहन डिजाइन कर रहे हैं और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नेविगेशन की सेवा करने वाले एप्लिकेशन विकसित कर रहे हैं। ये स्टार्टअप न केवल तकनीक बना रहे हैं, बल्कि वे रोजगार भी पैदा कर रहे हैं, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में युवा इंजीनियरों और उद्यमियों के लिए नये अवसर बन रहे हैं।

> **2014 से शुरू किए गए सुधारों ने नए आयाम खोले हैं। 2020 में IN-SPACe के निर्माण ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी, जिससे नवाचार की लहर उठी। आज, 300 से अधिक स्पेसटेक स्टार्टअप उपग्रह बना रहे हैं, लॉन्च वाहन डिजाइन कर रहे हैं और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नेविगेशन की सेवा करने वाले एप्लिकेशन विकसित कर रहे हैं**

उदारीकृत नीति ने अंतरिक्ष सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बना दिया है, जिससे उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है। भारत के उपग्रह अब मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे किसानों को अधिक सटीकता के साथ अपनी बुवाई और कटाई चक्र की योजना बनाने में मदद मिलती है। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में उपग्रह डेटा प्रारंभिक चेतावनी और आपदा प्रतिक्रिया को कारगर बना रहे है, जिससे जीवन और आजीविका को लाभ मिलता है। चक्रवातों और सूखे के दौरान रिमोट सेंसिंग अधिकारियों को नुकसान की तैयारी और उसे कम करने में मदद करती है। ग्रामीण क्लीनिकों में उपग्रह कनेक्टिविटी द्वारा संचालित टेलीमेडिसिन सेवाएं अब शहरी अस्पतालों के डॉक्टरों को दूरदराज के क्षेत्रों में रोगियों के साथ जुड़ने और उन्हें परामर्श प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहे है, जिससे स्वास्थ्य सेवा की खाई कम हुई है। सैटेलाइट बैंडविड्थ द्वारा समर्थित ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म दूरदराज के गांवों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

भारत का स्वदेशी जीपीएस नेटवर्क, NavIC सिस्टम, अब वाहनों में नेविगेशन, ट्रेनों और जहाजों पर नजर रखने और यहां तक कि मछुआरों को सुरक्षित रूप से किनारे पर वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उपग्रह के माध्यम से किसानों को मिट्टी की नमी, फसल के स्वास्थ्य और कीटों के संक्रमण की निगरानी करने में मदद मिल रही है, जिससे बेहतर निर्णय और बेहतर पैदावार संभव हो पाती है। ये अमूर्त लाभ नहीं हैं— ये लाखों लोगों के जीवन में वास्तविक लाभ हैं। पिछले दशक में लॉन्च किए गए मिशनों ने वैश्विक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। मंगलयान अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंच गया, जिसने भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता साबित हुई। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा, ऐसा क्षेत्र जहां पानी होने का अनुमान है और इसके रोवर ने ऐसे प्रयोग किए जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए मददगार होंगे। आदित्य-एल1 सौर तूफानों का अध्ययन कर रहा है, जिससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के मौसम और संचार

प्रणालियों और बिजली ग्रिड पर इसके प्रभाव को समझने में मदद मिल रही है। 2027 के लिए निर्धारित गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा लेकिन चालक दल की उड़ान से पहले ही यह मिशन नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है।

अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रणालियों का विकास, तथा बिना चालक दल के परीक्षण उड़ानें प्रभावशाली असर पैदा कर रही है - अनुसंधान को बढ़ावा दे रही हैं, प्रतिभाओं को आकर्षित कर रही हैं, तथा राष्ट्रीय गौरव का निर्माण कर रही हैं। भविष्य को देखते हुए भारत 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है तथा अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग की हाल की सफलता ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को सिद्ध किया है। यह स्टेशन दीर्घकालिक निवास तथा अनुसंधान की अनुमति देगा, जिससे गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरग्रहीय मिशनों के लिए द्वार खुलेंगे। इन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए भारत अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) विकसित कर रहा है, जो 30,000 किलोग्राम वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम है। इसमें पुनः प्रयोज्य चरण तथा मॉड्यूलर प्रणोदन प्रणाली होगी, जिससे अंतरिक्ष तक पहुंच अधिक किफायती तथा टिकाऊ होगी।

भविष्य को देखते हुए भारत 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है तथा अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग की हाल की सफलता ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को सिद्ध किया है। यह स्टेशन दीर्घकालिक निवास तथा अनुसंधान की अनुमति देगा, जिससे गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरग्रहीय मिशनों के लिए द्वार खुलेंगे

प्रक्षेपणों की बढ़ती आवृत्ति को संभालने और वाणिज्यिक मिशनों का समर्थन करने के लिए श्रीहरिकोटा में एक तीसरा लॉन्च पैड और तमिलनाडु में एक नया स्पेसपोर्ट बनाया जा रहा है। नासा के साथ निसार मिशन पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक खतरों की निगरानी करेगा। जापान के साथ लूपेक्स मिशन एक भारी रोवर के साथ चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का पता लगाएगा। ये साझेदारियां एक विश्वसनीय वैश्विक अंतरिक्ष साझेदार के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं। लेकिन अंतरिक्ष केवल अन्वेषण के बारे में नहीं है— यह जिम्मेदारी के बारे में भी है। हजारों उपग्रहों के पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ अंतरिक्ष मलबा एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसरो का अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता कार्यक्रम वास्तविक समय में मलबे की निगरानी करता है, टकराव से बचने और अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रणनीति विकसित करता है। देश के हर कोने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रभाव दिखाई देता है।

आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल समावेशन का लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह एक शांत क्रांति हैं— जो बिना किसी दिखावे के जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसाकि हम अगले दशक की ओर देख रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट हैं: 2040 तक एक चालक दल के साथ चंद्रमा पर उतरना, एक पूरी तरह से कार्यात्मक अंतरिक्ष स्टेशन और वैश्विक अंतरिक्ष नवाचार में नेतृत्वकर्ता की भूमिका। ये केवल सपने नहीं हैं— ये उस राष्ट्र के लिए रणनीतिक अनिवार्यताएं हैं जिसने हमेशा समाज को बदलने के लिए विज्ञान की शक्ति में विश्वास किया है। थुंबा के साइकिल शेड से लेकर अंतरिक्ष की कक्षा में डॉकिंग तक, भारत की अंतरिक्ष यात्रा कल्पनाशीलता और अथक प्रयास से प्रेरित रही है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हर नागरिक, हर वैज्ञानिक, हर कल्पनाशील व्यक्ति को छूती है और जैसा कि हम मोदी सरकार के सफल ग्यारह सालों का जश्न मना रहे हैं, तो हम उस राष्ट्र को भी नमन करते हैं, जो वास्तव में सितारों तक पहुंचा और उनकी रोशनी को लेकर घर वापिस लौटा। ■

(लेखक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं।)

प्रधानमंत्री को 'ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III' से अलंकृत किया गया

साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने 16 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को साइप्रस के सम्मान 'ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III' से अलंकृत किया।

प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से यह सम्मान ग्रहण करते हुए साइप्रस के राष्ट्रपति, वहां की सरकार और लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह पुरस्कार भारत और साइप्रस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मधुर संबंधों को समर्पित किया जो साझा मूल्यों और आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह पुरस्कार भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' या 'विश्व एक परिवार है' के सदियों पुराने दर्शन की स्वीकृति है जो वैश्विक शांति व प्रगति के लिए इसके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करता है।

प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत और साइप्रस के बीच साझेदारी को मजबूत करने और विविधता लाने की नई प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह पुरस्कार शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और समृद्धि के लिए दोनों देशों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ■

7, लोक कल्याण मार्ग (नई दिल्ली) पर 10 जून, 2025 को विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

निकोसिया (साइप्रस) के ऐतिहासिक केंद्र में 16 जून, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडौलिडेस

कनानास्किस (कनाडा) में 17 जून, 2025 को आयोजित 51वें जी–7 शिखर सम्मेलन में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जगरेब (क्रोएशिया) में 18 जून, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते क्रोएशिया गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री आंद्रेज प्लेंकोविच

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में 21 जून, 2025 को 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, टीडीपी अध्यक्ष श्री चंद्रबाबू नायडू एवं अन्य विशिष्ट जन

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 03 जुलाई, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को विन्रम श्रद्धांजलि

छायाकार: अजय कुमार सिंह